सिटी चीफ

वर्ष-16, अंक-11
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं.

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 17 अप्रैल 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

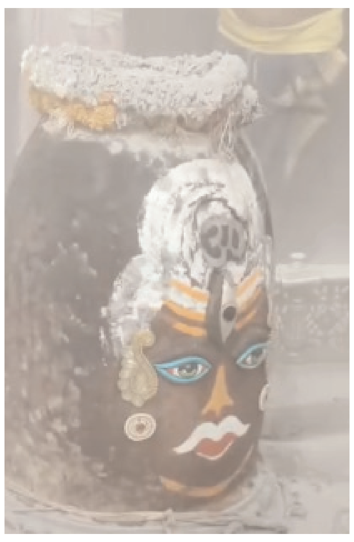

टोल वसूली का नया युग... मई से बिना फास्टैग के ही कट जाएगा टोल!

नई दिल्ली। देश के टोल बूथ को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव करने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश के राजमार्गों पर टोल पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। केंद्र अगले 15 दिनों के अंदर एक नई टोल पॉलिसी पेश करने वाली है। यानी मई से यह पॉलिसी लागू हो सकती है। हालांकि, गडकरी ने अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि एक बार नई पॉलिसी लागू होने के बाद टोल के बारे में किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इस नए सिस्टम से फास्टैग का काम भी खत्म हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि नए सिस्टम के लिए फिजिकल टोल बूथ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, सैटेलाइट ट्रैकिंग और व्हीकल नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके बैंक खातों से टोल ऑटोमैटिक ही पेमेंट कट जाएगा। उन्होंने लंबे समय से लंबित मुंबई-गोवा हाईवे पर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना इस साल जून तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर कई कठिनाइयां थीं, लेकिन चिंता न करें हम इस जून तक सड़क का 100 फीसदी काम पूरा कर लेंगे।

इस तरह काम करेगा जीपीएस टोलिंग सिस्टम देश में सड़कों के निर्माण के साथ टोल बूथ की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार बूथों को समाप्त करने जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के फास्टैग सिस्मट को रिप्लेस करने वाली है। टोल बूथ का निर्माण से इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे टोल कलेक्शन की लागत में भी बढ़ोतरी होती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार नया टोलिंग सिस्टम लाने वाली है। इस सिस्टम में जीपीएस की मदद से सीधे ड्राइवर या व्हीकल ऑनर के बैंक अकाउंट से टोल की राशि काटी जाएगी। व्हीकल की निगरानी जीपीएस के माध्यम से होगी। तय किए गए मार्जिन और समय के आधार पर टोल की राशि कैलकुलेट की जाएगी।

3000 रुपए में सालभर सफर नई टोल पॉलिसी के तहत एनुअल पास बनेंगे। यानी एक बार पास बनवाया तो सालभर टोल टैक्स भरने की छुट्टी। नई टोल पॉलिसी आपकी जेब पर बोझ कम करने वाली है, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। एनुअल पास की मदद से आप बिना रोक-टोक हाईवे-एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। नए टोल सिस्टम के तहत अब किलोमीटर बेस्ड चार्जिंग सिस्टम लागू होगा।

देशभर के टोल प्लाजा हटेंगे नई टोल पॉलिसी से हाईवे, एक्सप्रेसवे पर सफर का मजा अब और बढ़ जाएगा। अब लंबी ड्राइव के दौरान आपको टोल प्लाजा पर बार-बार रुकना नहीं होगा। एक बार फर्राटे से कार ने रफ्तार भरी तो सीधे मंजिल पर जाकर रुकेंगे। सफर के दौरान टोल प्लाजा की बाधा अब खत्म होने वाली है। नए टोल सिस्टम के तहत देशभर में टोल प्लाजा हटेंगे।

जितना चालाओ, उतना देना होगा टैक्स नई टोल पॉलिसी के तहत किलोमीटर बेस्ड चार्जिंग सिस्टम लागू होगा। यानी आप जितना किलोमीटर गाड़ी भगाओगे उतना ही टोल टैक्स भरना होगा। एनुअल टोल पास की भी सुविधा होगी। 3000 रुपए में एनुअल टोल पास मिलेगा। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार नई कार के साथ लाइफटाइम टोल प्लाजा पास पर भी विचार कर सकती है। 30 हजार में 15 सालों तक किसी भी टोल प्लाजा पर फ्री होकर आना-जाना कर सकते हैं। हालांकि लाइफटाइम पास को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

एटीएम ऑन व्हील्स: भारतीय रेलवे ने डिजिटल भारत की दिशा में उठाया क्रांतिकारी कदम

देश में पहली बार ट्रेन में लगा एटीएम चलती गाड़ी में कैश निकाल पाएंगे यात्री

नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को कभी कैश की दिक्कत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने रेलगाडियों में एटीएम लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल भारत की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। पहली बार, महाराष्ट्र में चलने वाली गाड़ी संख्या 12110 (मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस) में एक टेस्ट के आधार पर एटीएम ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है। यह पहल रेलवे के गैर-किराया राजस्व को बढ़ावा देने और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर इस मोबाइल एटीएम का वीडियो साझा किया है, जिससे यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस एटीएम को ट्रेन की मिनी पेंट्री को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है, जिसे रबर पैड और बोल्ट की सहायता से कंपन से सुरक्षित किया गया है। साथ ही, दो अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। यदि यह नई सुविधा यात्रियों के बीच सफल रहती है, तो भारतीय रेलवे अन्य ट्रेनों में भी इस तरह की सुविधाएं शुरू करने पर विचार करेगा।

यह है रेलवे का मकसद एटीएम ऑन व्हील्स पहल रेलवे बोर्ड के उस निर्देश का हिस्सा है जिसमें कहा गया था कि किराए के अलावा कमाई बढ़ाने के लिए नई सोच के तरीके अपनाए जाएं। इसी के तहत 25 मार्च 2025 को रेलवे ने सभी संभावित वेंडरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में चलती ट्रेनों में मोबाइल एटीएम लगाने का विचार रखा गया, जिसे बाद में मंजूरी भी मिल गई। भारतीय रेलवे विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए लगातार आधुनिकीकरण और इनोवेशन की दिशा में कार्य कर रही है। आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक ट्रेनें, और नई सुरक्षा प्रणालियां इस परिवर्तन की पहचान हैं।

इस तरह हुआ ट्रायल ट्रेन में एटीएम का का पहला ट्रायल मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया। ट्रेन के मिनी पैंट्री (छोटे किचन) वाले हिस्से को एटीएम लगाने के लिए तैयार किया गया। रेलवे की मैकेनिकल टीम ने यह काम किया और एटीएम को सुरक्षित रूप से फिट किया। रबर पैड और बोल्ट्स की मदद से एटीएम को ट्रेन के चलने के दौरान लगने वाले झटकों और कंपन से बचाया गया। दो अग्निशमन यंत्र भी उस जगह पर लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे। ट्रेन में एटीएम लगाने से यात्रियों को कहीं भी आते-जाते पैसे निकालने की सुविधा देना है। इसके अलावा किराए के अलावा रेलवे को अतिरिक्त कमाई का जरिया मिलना और साथ ही रेलवे को और आधुनिक और स्मार्ट बनाना है।

भुसावल रेलवे डिवीजन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी यह नई सुविधा भुसावल रेलवे डिवीजन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी में शुरू की गई है। भुसावल डीआरएम के अनुसार, इस नई सुविधा के शुरुआती नतीजे काफी सकारात्मक रहे हैं। मशीन की कार्यक्षमता पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे नकद निकासी में परेशानी हो सकती है।

कोच के पिछले हिस्से में लगाया गया एटीएम रेलवे अधिकारियों के अनुसार, एटीएम को कोच के पिछले हिस्से में लगाया गया है, जो पहले अस्थायी पेंट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने बताया कि ट्रेन के चलने के दौरान सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक शटर दरवाजा भी लगाया गया है। सुरक्षा के प्रबंधों के तहत एटीएम में सीसीटीवी निगरानी, और तकनीकी सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने आगे बताया कि कोच में आवश्यक संशोधन मानमाड रेलवे वर्कशॉप में किया गया।

पंचवटी एक्सप्रेस की खासियत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पड़ोसी नासिक जिले के मनमाड जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस अपनी एकतरफा यात्रा लगभग 4.35 घंटे में पूरी करती है। यह इंटरसिटी यात्रा के लिए सुविधाजनक समय के कारण इस मार्ग की लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है।

सिर्फ कैश नहीं, मिलेंगी और भी बैंकिंग सुविधाएं पंचवटी एक्सप्रेस की सभी 22 बोगियां वेस्टिब्यूल से जुड़ी हुई हैं, जिससे किसी भी डिब्बे का यात्री एटीएम सुविधा का लाभ उठा सकता है। खास बात यह है कि यही एटीएम अब मुंबई-हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि दोनों ट्रेनों में एक ही रैक का उपयोग किया जाता है। इस एटीएम से यात्री केवल नकदी नहीं निकाल सकेंगे, बल्कि वे चेक बुक मंगवाने, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा के लिए मुगल 'वंशज' ने यूएन प्रमुख को लिखा पत्र

मुंबई। बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यह मांग उस हिंसा के लगभग एक महीने बाद सामने आई है, जो नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग वाली एक रैली के दौरान भड़क उठी थी। याकूब तुसी खुद को औरंगजेब की कब्र वाली वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली भी बताते हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि यह कब्र एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संरक्षित स्मारक के पास या आसपास कोई अनधिकृत निर्माण, परिवर्तन, विनाश या उत्खनन नहीं किया जा सकता, और ऐसा कोई भी कार्य अवैध माना जाएगा और कानून के तहत दंडनीय होगा।

इमामों के सम्मेलन में भड़की ममता बनर्जी बोलीं- योगी सबसे बड़ा 'भोगी'

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट को लेकर इमामों के साथ एक बैठक के दौरान भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। ममता ने यूपी से सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सबसे बड़ा 'भोगी' है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर उनके राज्य में हुई हिंसा पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। योगी ने कहा था कि बंगाल जल रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री चुप है। वह दंगाइयों को 'शांति का दूत' कहती हैं। लेकिन जो लोग केवल बल को समझते हैं, वे शब्दों को नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को अशांति फैलाने की पूरी आजादी दे दी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक हफ्ते से जल रहा है, फिर भी सरकार चुप है।

जस्टिस बीआर गवई होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस

सीजेआई संजीव खन्ना ने की सिफारिश

नई दिल्ली। जस्टिस बीआर गवई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज बीआर गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। जस्टिस गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। बीआर गवई 14 मई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस खन्ना ने नवंबर 2024 में सीजेआई का पद संभाला था। भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर, 1960 को अमरावती में हुआ था। वे 16 मार्च, 1985 को बार में शामिल हुए थे। जस्टिस गवई लगभग छह महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस गवई नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद वे चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गवई राज्य में हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ काम किया इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। उसके बाद, उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की जस्टिस गवई अगस्त 1992 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 2000 में उन्हें नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नामित किया गया। जस्टिस गवई 2003 में हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने। 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया।

ट्रैफिक सिग्नल पर सरकारी बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, तीन की मौत

राजकोट। गुजरात के राजकोट शहर में बुधवार सुबह स्थानीय नगर निगम की ओर से संचालित तेज रफ्तार बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर कई वाहनों और पैदल यात्रियों को कुचल दिया। इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में इलेक्ट्रिक बस को व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर दोपहिया और कारों सहित वाहनों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस उपायुक्त (जोन -2) जगदीश भांगरवा ने बताया कि राजकोट नगर निगम (आरएमसी) की ओर से संचालित एक इलेक्ट्रिक सिटी बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर कई लोगों को कुचल दिया। इस दौरान बस ने कई चारपहिया और दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बस ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ पैदल यात्रियों सहित कई वाहनों को चपेट में लिया। यह दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे इंदिरा सर्किल पर हुई। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की। जब बस दुर्घटनास्थल से कुछ दूरी पर रुकी तो लोगों ने इसे घेर लिया और जमकर बस पर पत्थर बरसाए।

सुप्रीम सुनवाई शुरू- वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार...लेकिन पूछा बड़ा सवाल

क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर सौ से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकीलों ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई। वक्फ कानून पर दो घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने जा रहा था। सीजेआई ने पहले कहा कि हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा... चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं... लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा।। बोर्ड और परिषद के संबंध में... पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को भी होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।

वक्फ बाय यूजर का मसला भी उठा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि वक्फ बोर्ड में दो गैर मुसलमानों को शामिल करने की बात कही गई है, तो क्या हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में सरकार मुसलमानों को शामिल करेगी वक्फ (संशोधन) अधिनियम में यह प्रावधान है कि 22 नियुक्त सदस्यों में से दो गैर मुसलमान होंगे, वहीं राज्य के बोर्ड में भी दो गैर मुसलमानों को नियुक्त करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाय यूजर का मसला भी उठा, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को हटा रहे हैं, तो यह एक मसला है। देश में अधिकतर वक्फ मस्जिदें 14वीं और 15वीं सदी में बनी हैं और अब उनका डीड मांगना सही नहीं होगा, क्योंकि वह किसी के पास मौजूद नहीं होगा। कोर्ट ने इन्हीं दो मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

सब्जी बेचने वालों पर टूट पड़ा निगम का अमला, 12 ट्रक माल जब्त

इंदौर। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अमला बुधवार शाम को कार्रवाई करने पहले महू नाका फिर दशहरा मैदान पहुंचा। यहां सब्जी बेचने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। सब्जी वालों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन निगम टीम और पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली। निगम के अमले ने यहां से सब्जियां, ठेले व अन्य सामान सहित करीब 12 ट्रक माल जब्त किया है। जो सब्जियां यहां से जब्त की गई है उसे चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। नगर निगम को महू नाका चौराहे के समीप सब्जी बेचने-खरीदने वालों के कारण रोज शाम को ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। प्रभारी अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि यहां पर ट्रैफिक के कारण लोग काफी परेशान होते थे। शाम को बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की थी। शाम को सिंगल गाड़ी निकलने में भी दिक्कत होती थी। पिछले कुछ महीने से कार्रवाई का प्लान चल रहा था। लगातार हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया जा रहा था। मंगलवार को भी अनाउंसमेंट किया था। जिन्होंने अपना सामान हटा लिया था, उन्हें छोड़कर बाकी सभी का सामान कार्रवाई में जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महू नाका और दशहरा मैदान दोनों जगह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 12 ट्रक सामान जब्त किया गया है। महू नाका पर बहुत से लोगों ने झोपड़े जैसा निर्माण भी कर लिया था। वहां लोग रहने भी लग गए थे। उन्हें भी तोड़ने की कार्रवाई की गई है। विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जो सब्जियां जब्त की हैं उन्हें चिड़ियाघर भेजा जाएगा। बाकी जो सामान है वह नियमानुसार छोड़ा जाएगा। कार्रवाई के दौरान यहां पर हंगामे की स्थिति भी बनी। टीम जब कार्रवाई करने लगी तो सब्जी वालों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया। इस दौरान टीम और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। सब्जी वालों ने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई। एक महिला ने गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब लोग कहा जाएंगे। हमारे जैसे धूप में बैठकर देखो। बताया जा रहा है कि कार्रवाई का विरोध करने के लिए महिला ने एसिड की बॉटल लाकर पीने की कोशिश की, लेकिन निगमकर्मियों ने उससे बॉटल छिन ली।

इधर, दूसरी कार्रवाई में निगम की टीम ने जोन 13 में आने वाले गोकुल गार्डन पर 1 लाख रुपए का स्पाट फाइन लगाया। जोनल अधिकारी अंकेश बिरथरिया ने बताया कि शिकायत मिली थी इस क्षेत्र में मिक्स कचरा फेंका जा रहा था। जिस पर जांच में पाया गया कि गोकुल गार्डन से निकलने वाले मिक्स कचरे को यहां-वहां फेंका जा रहा है। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशन में गोकुल गार्डन के प्रबंधक मनोज चौहान पर एक लाख रुपए का स्पाट फाइन किया गया।

बीआरटीएस तोड़ने से नगर निगम कमाएगा करोड़ों रुपए

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने बीआरटीएस कॉरिडोर के संपूर्ण सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस सर्वे में यह स्पष्ट हो गया है कि इस कॉरिडोर को तोड़ने में कितनी लागत आएगी और मलबा एवं अन्य सामग्री की बिक्री से कितनी आय होगी। सर्वे के अनुसार, कॉरिडोर को तोड़ने में लगभग 34.70 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि मलबा और अन्य सामग्री की बिक्री से निगम को लगभग 3.71 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया से शुद्ध लाभ के रूप में निगम को 3.37 करोड़ रुपए की कमाई होगी। राज्य सरकार द्वारा कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसे हाईकोर्ट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब नगर निगम द्वारा तोड़ाई की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

कॉरिडोर तोड़ने में आएगा इतना खर्च

सर्वे के मुताबिक, कॉरिडोर में आरसीसी बीम की कुल लंबाई 10475 मीटर, चौड़ाई 0.35 मीटर तथा गहराई 0.30 मीटर है, जिसका कुल घनफल 2199 घनमीटर है। इसे हटाने की लागत प्रति घनमीटर 786 रुपए के अनुसार 17.29 लाख रुपए होगी। वहीं, 18 बस शेल्टर होम की कुल लंबाई 344 घनमीटर है, जिस पर 8.20 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे आरसीसी निर्माण 32207 घनमीटर क्षेत्र में फैले हैं और स्क्रब्स 40105 घनमीटर में निर्मित हैं। इन निमार्णों को हटाने पर 3.25 लाख रुपए का खर्च आएगा। कॉरिडोर के दोनों ओर लगी स्टील की रैलिंग, जिनका कुल क्षेत्रफल 3.67 लाख वर्गमीटर है, इन्हें निकालने पर भी कुछ खर्च आएगा। कुल मिलाकर यह पूरा कार्य 34.70 लाख रुपए में संपन्न होगा।

मलबा और सामग्री से होगी करोड़ों की कमाई

नगर निगम द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार, कॉरिडोर से लगभग 1.53 लाख किलो स्टील निकलेगा, जिसकी बिक्री से 46 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, 10000 मीटर लंबाई की रैलिंग और 90 प्रतिशत ए-श्रेणी का स्क्रैप मटेरियल निकलेगा, जिसकी बिक्री 45 रुपए प्रति किलो की दर से की जा सकेगी और इससे 2.31 करोड़ रुपए की कमाई होगी। वहीं, बस शेल्टर होम में प्रयुक्त अतिरिक्त आइटम की बिक्री से 90 लाख रुपए की आय होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर निगम को 3.71 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

दो महीने में होगा काम पूरा, टेंडर प्रक्रिया जल्द

नगर निगम जनकार्य विभाग के प्रभारी और महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर ने जानकारी दी कि कॉरिडोर को तोड़ने में लगभग दो महीने का समय लगेगा। निगम अब जल्द ही इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। ठेकेदारों को यह प्रस्ताव देना होगा कि वे तोड़ाई के काम के बदले निगम को कितनी राशि देंगे। जो ठेकेदार अधिकतम राशि का ऑफर देगा, उसे यह ठेका दिया जाएगा। ठेकेदार को ही मलबा और मटेरियल भी मिलेगा। निगम को कम से कम 3.37 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रक्रिया से निगम को आर्थिक लाभ के साथ शहर के विकास कार्यों के लिए भी नई राह मिलेगी।

इंदौर की बारात में धूप से बचने के लिए चलते-फिरते टेंट का इस्तेमाल

इंदौर। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए इंदौर से एक राहत भरी और बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है। खजराना क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में बारात को लेकर जो अनूठा इंतजाम किया गया, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। शादी में शामिल मेहमानों को गर्मी से बचाने के लिए एक परिवार ने ऐसा उपाय किया, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। इस बारात की खास बात यह रही कि इसमें एक चलता-फिरता टेंट लगाया गया, जो बारात के साथ-साथ आगे बढ़ता रहा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज धूप में निकली बारात के ऊपर एक बड़ा तंबू लगाया गया है, जो बारातियों को चिलचिलाती धूप से राहत दे रहा है। इस टेंट के नीचे न केवल बाराती चल रहे हैं, बल्कि दूल्हा भी घोड़ी पर सवार होकर उसी के अंदर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं। अब शादी में जाना है तो ऐसी ही बारात में।

बता दें कि इस समय देश के अनेक हिस्सों में लू और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में विवाह समारोहों में मेहमानों की उपस्थिति भी कम हो रही है। लेकिन इंदौर के पटेल परिवार ने अपने मेहमानों को इस तपती गर्मी से बचाने के लिए नायाब इंतजाम किया। इससे पहले भी इंदौर में एक होटल व्यवसायी ने अपनी शादी में चलित कूलरों का इंतजाम कर गर्मी से निपटने का अनोखा तरीका अपनाया था। अब इस चलित टेंट वाली बारात ने फिर साबित कर दिया कि इंदौर न केवल सफाई में नंबर वन है, बल्कि नवाचार और स्मार्ट सोच में भी अव्वल है।

3 दिन तक तपेंगे मप्र के 19 जिले

मध्यप्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है और मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। रतलाम में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं चार महानगरों में इंदौर सबसे गर्म रहा, यहां भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। साथ ही धार में 41.2, खंडवा में 41.1, उज्जैन में 40.8, भोपाल में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले तीन-चार दिनों से प्रदेश में बादल, बौछारों की स्थिति थी, इसके कारण तापमानों में थोड़ी नमी थी, लेकिन अब सिस्टम कमजोर पड़ने के साथ ही फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। राजस्थान, गुजरात से फिर गर्म हवा आने लगी है। ऐसे में इन दिनों मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गए है। 19 जिलों में अब तेज गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट है। मौसम विज्ञानी ने बताया, प्रदेश में जो सिस्टम बने थे, वह कमजोर हो गए हैं। इस समय हवा का रूख उत्तर पश्चिमी है। ऐसे में अगले तीन चार दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल तक गर्मी बढ़ने अनुमान जताया है। इस बीच बारिश की संभावना बहुत कम है। आने वाले तीन दिनों में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश में 16 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। जिसका असर दो दिन बाद 19 अप्रैल से दिखेगा। ऐसे में पारा 2 से 3 डिग्री गिर सकता है।

रतलाम के सैलाना में बारिश, पर सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं

मंगलवार को मध्यप्रदेश में तेज गर्मी का व्यापक असर देखा गया। कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इसी दौरान रतलाम जिले के सैलाना में दोपहर के समय हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि बारिश के बावजूद सैलाना में ही सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को रतलाम में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे अधिक था।

कई इलाकों में छाने लगा जलसंकट

टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी

इंदौर। तापमान बढ़ने के साथ ही इंदौर में जलसंकट गहराने लगा है। शहर के कई इलाकों में टैंकरों से जल वितरण करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बोरिंगों का बंद होना है। इंदौर में ज्यादातर घरों में बोरिंगों से जलापूर्ति हो जाती है। गर्मी में कई बोरिंगों ने या तो पानी देना बंद कर दिया है या फिर उनमें पानी का दबाव कम हो गया है। इस कारण शहर के ज्यादातर इलाके नर्मदा जल पर निर्भर हो चुके हैं। शहर में रोज जलापूर्ति होती है, लेकिन नलों में भी पानी का प्रेशर कम हो गया है। लोग पंप लगाकर पानी खींचते हैं। इस कारण दूसरे घरों में नल नहीं आते हैं। जलसंकट को देखते हुए नगर निगम ने 100 से ज्यादा टैंकर किराए पर ले रखे हैं। हर वार्ड में एक टैंकर जल वितरण के लिए भेजा है। जो वार्ड क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। वहां दो टैंकरों की डिमांड आने लगी है। शहर की कई कॉलोनियों में पानी ठीक से नहीं मिलने की समस्या को देखते हुए हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव बिजलपुर स्थित नर्मदा नियंत्रण कक्ष पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने

पानी की टंकियों में वितरण के सिस्टम को मॉनिटरिंग व्यवस्था का अवलोकन किया। वांचू पाइंट से पानी कम क्यों आ रहा है, इसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए। उन्होंने इंदौर तक आने वाले पानी की चोरी को रोकने के लिए भी कहा है। महापौर ने कहा कि मेरे लिए पूरा शहर एक समान है, इसलिए टंकियों में पानी के वितरण में कोई भी अधिकारी, पार्षद पक्षपात न करे।

अहिरखेड़ी में बसाए गए परिवार हो रहे परेशान इंदौर में नगर निगम ने कई गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर फ्लैट दिए। सड़क के लिए उनके घर उजाड़े तो भी उन्हें बदले में शहर के अलग-अलग स्थानों पर फ्लैट दिए, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। इंदौर की अहिरखेड़ी में बसाए गए परिवार जलसंकट झेल रहे है। यहां तीन सौ से ज्यादा परिवारों के लिए फ्लैट बनाए गए है, लेकिन पानी के लिए मल्टियों में टंकियां नहीं रखी। जो बोरिंग कराए है। उनमें भी पानी काफी कम आ रहा है। इस कारण यहां रहने वाले परिवारों को पानी दूर से लाना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम अफसरों को पानी के टैंकरों के लिए कई बार फोन लगाना पड़ते है। टैंकर आते भी है तो पहले पानी भरने के चक्कर में परिवार आपस में लड़ने लगते है। लोगों ने पानी के लिए कोठियां ले रही है।

एमटीएच अस्पताल भी टैंकरों के भरोसे

एमजीएम कॉलेज के अंतर्गत आने वाले एमटीएच अस्पताल में भी पानी की किल्लत से मरीज परेशान हो रहे है। यहां रोज पानी की आपूर्ति नगर निगम के टैंकरों के भरोसे हो रही है। गर्मी में यहां के बोरिंग साथ छोड़ देते है। पिछले साल तो जलसंकट के कारण यहां सर्जरी प्रभावित होने लगी थी। डॉक्टरों को हाथ धोने के लिए पानी नहीं रहता था। सर्जरी के बाद वे स्पीरिट से हाथ धोते थे। डाक्टरों का कहना है कि यहां रोज सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते है। नगर निगम को यहां नर्मदा का बड़ा कनेक्शन देना चाहिए, ताकि मरीजों को भी परेशान न होना पड़ा। शौचालयों में पानी नहीं होने के कारण मरीज व उनके परिवारों को परेशान होना पड़ता है।

जहां चलेगी मेट्रो ट्रेन, वहां आबादी ही नहीं

इंदौर। सुपर कॉरिडोर पर छह किलोमीटर लंबा रूट मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने किराया भी तय कर दिया है। मेट्रो का संचालन कब से शुरू होगा। यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन गांधी नगर डिपो से बड़ा बांगड़दा तक जिस हिस्से में मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा, वहां आबादी ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मेट्रो को यात्री कैसे मिलेंगे?मेट्रो के पहले रूट पर न तो अभी बसाहट हुई है और न ही कोई व्यापारिक क्षेत्र है। इसके चलते अभी उस रुट पर मेट्रो के लिए यात्री मिलना मुश्किल है। अभी सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस और इंफोसिस के बड़े कैम्पस हैं। उनमें काम करने वाले कर्मचारी भी एरोड्रम क्षेत्र, सुखलिया ग्राम या विजय नगर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मेट्रो के मौजूदा रूट में ये इलाके नहीं हैं। इस कारण इन कंपनियों के कर्मचारियों को भी मेट्रो ट्रेन का ठीक से फायदा नहीं मिल पाएगा। यदि मेट्रो ट्रेन गांधी नगर से विजय नगर तक संचालित होती है तो फिर यात्री बढ़ सकते हैं, क्योंकि गांधी नगर क्षेत्र के कई लोग काम के सिलसिले में विजय नगर या उससे आगे जाते हैं। उनके लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेट्रो लाइन के शहर के मध्य हिस्से में अंडरग्राउंड काम होना है। इसके लिए टेंडर भी मंजूर हो चुके हैं। कंपनियों को भी कार्य आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व अन्य जनप्रतिनिधियों को नाथ मंदिर से मेट्रो के अंडरग्राउंड किए जाने पर आपत्ति है। उनका कहना है कि मेट्रो बंगाली कॉलोनी चौराहा से ही अंडरग्राउंड हो ताकि पलासिया चौराहे पर ब्रिज बनाने या भविष्य में होने वाले अन्य निर्माण के लिए परेशानी न हो। अभी मेट्रो का काम गांधी नगर से एमआर-9 चौराहे तक ही चल रहा है। उससे आगे काम नहीं हो रहा है।

पत्नी के सुसाइड में पति पर एफआईआर

इंदौर। इंदौर की खुड़ैल पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में उसके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों के बयान लिए थे। जिसमें पति द्वारा आए दिन झगड़ा और मारपीट करने की बात सामने आई थी। इससे डिप्रेशन में आकर महिला ने सुसाइड कर लिया था।

प्रियंका मंडलोई के सुसाइड में पुलिस ने उसके पति भूपेन्द्र मंडलोई, निवासी मूसाखेड़ी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। प्रियंका ने 25 मार्च 2025 को जहर खा लिया था। उसे उपचार के लिए बालाजी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी। दोनों की शादी 2005 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। पुलिस ने उसकी मौत के बाद मां माया, पिता सुदामा, बड़े पिता जगदीश, भाई धर्मेंद्र व अन्य लोगो सहित बेटे के बयान लिए थे। परिजन ने अपने बयान में बताया कि बेटी प्रियंका ने बताया था कि भूपेन्द्र आए दिन विवाद करता था। झगड़े और मारपीट से तंग आकर बेटी कई बार मायके आई। तब माफी मांगने पर दामाद के साथ वापस भेज दिया। 25 मार्च को भूपेन्द्र कार से बेटी प्रियंका को लेकर घर आए। उसे अपशब्द कहते हुए चांटे मारे। तब बेटी ने चिल्लाते हुए कहा कि पति जान से मार देगा। उसने अभी सल्फास खिला दी है। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे लेकर बालाजी अस्पताल आए। यहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

25 लाख पौधे लगाने के लिए जमीन की तलाश बड़ी चुनौती

इंदौर। वन विभाग पिछले कई दिनों से लगभग 25 लाख पौधे लगाने के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल संसाधन मंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत इंदौर वन विभाग को 25 लाख पेड़-पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है।मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश के बाद वन विभाग ने महू, मानपुर, चोरल सहित इंदौर फॉरेस्ट रेंज में पौधे लगाने के लिए स्थानों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा के अनुसार, कई स्थानों की पहचान कर ली गई है, जहां पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। हालांकि वन विभाग के

कर्मचारियों का कहना है कि 25 लाख नए पौधे लगाने के लिए जमीन तलाशना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आदेश पर 51 लाख पौधारोपण अभियान चलाया गया था, जिसमें विभाग ने लगभग 25 लाख पौधे पहले ही लगा दिए थे।

हर साल 5 लाख पौधारोपण की परंपरा

इसके अलावा, वन विभाग हर साल वर्षा ऋतु से पहले लगभग 5 लाख पौधे स्वयं भी लगाता है। इस वर्ष भी बारिश से पहले गड्ढे खोदने की तैयारियाँ जोरों पर हैं। ऐसे में इस बार पौधों की संख्या और जिम्मेदारी दोनों ही अधिक हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अब पूरा वन अमला इंदौर की चारों फॉरेस्ट रेंजों में पौधारोपण के लिए जगह तलाशने में व्यस्त है। यह अभियान विभाग के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और जमीनी चुनौती बन चुका है।

30 लाख पौधे लगाने की बड़ी जिम्मेदारी

पिछले वर्ष के अभियान के बाद इस साल भी इंदौर वन विभाग के सामने करीब 30 लाख पेड़-पौधे लगाने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग कितने समय में 25 लाख पौधों के लिए जमीन का बंदोबस्त कर पाता है। उल्लेखनीय है कि शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी होती है। जल गंगा संवर्धन अभियान भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

पुलिस ने रोका तो सड़क पर लेटे कांग्रेसी

पिंजरे में तोता लेकर भोपाल के ईडी कार्यालय पहुंचे पीसीसी चीफ

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। नेशनल हेराल्ड मामले में हुई कार्रवाई को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता विरोध दर्ज कर रहे हैं। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जीतू पटवारी पिंजरे में प्रतीकात्मक तोता लेकर पहुंचे। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अफसरों ने बीएसएनएल मुख्यालय का मेन गेट बंद कर दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को ईडी ऑफिस तक नहीं जाने दिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तपती धूप में सड़क पर ही लेटकर नारेबाजी करने लगे।

ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए विपक्ष को कर रहे परेशान
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्ज शीट पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ पटवारी प्रवर्तन निदेशालय की दफ्तर पर पिंजरे में प्रतीकात्मक तोता लेकर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने बीएसएनएल ऑफिस के बाहर पुलिस अफसर को ज्ञापन के साथ ही पिंजरे में रखा तोता भी भेंट किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था मोदी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए विपक्ष को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने तोते की तरह ईडी को अपने कैद में कर रखा है।

सड़क पर लेटे कार्यकर्ता
पुलिस ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईडी ऑफिस तक नहीं जाने दिया तो प्रदर्शनकारी तपती धूप में सड़क पर ही लेटकर नारेबाजी करने लगे। बीएसएनएल ऑफिस के बाहर लगा ईडी ऑफिस का बोर्ड पुलिस ने कांग्रेसियों के पहुंचने के पहले ही ढंक दिया। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीएसएनएल ऑफिस के बाहर पहुंचे तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव, सोनू तोमर ने ईडी ऑफिस के बोर्ड से बैनर हटाने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। इस दौरान थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई

मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार चार्जशीट दाखिल हुई थी
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ आज भोपाल सहित प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी।

10वीं 12वीं का 85 फीसदी मूल्यांकन कार्य पूरा, मई में आएगा रिजल्ट

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। एमपी बोर्ड से इस वर्ष 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्द ही परीक्षा परीणाम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा मूल्यांकन पर पूरा फोकस किया। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन अंतिम दौर में है। लगभग 85 फीसदी कॉपियों की जांच कर ली गई है। 20 अप्रैल तक कॉपियों की जांच पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। गौरतल है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की थी, तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जाए।

जुलाई में होगी दूसरी परीक्षा
नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की जुलाई में दूसरी परीक्षा कराई जानी है। उसकी तैयारी के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। सीएम का निर्देश प्राप्त होने के बाद मंडल अधिकारियों ने मूल्यांकन पर पूरा फोकस किया है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 85 फीसदी कंपलीट हो गया है जबकि दसवीं की परीक्षा कापियों की जांच 82 प्रतिशत पूर्ण हो गई है। संपूर्ण मूल्यांकन में चार-पांच दिन का समय और लगेगा। इसके बाद रिजल्ट तैयार होगा।

अगली परीक्षा की तैयारी शुरू, जल्द आएगा टाइम टेबल
बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट तय समय में घोषित होगा। रिजल्ट जारी करने के बाद अगली परीक्षा की तैयारियां की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की तैयारियां प्रारंभकर दी गई हैं। इस पर निरंतर काम चल रहा है। जुलाई में जो परीक्षा होने जा रही हैं। शीघ्र ही इसका टाइम टेबल घोषित किया जाएगा।

16 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने दिया परीक्षा
गौरतलब है कि इस सत्र में दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 16,60,252 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। इसमें से 12वीं क्लास में 7,06,475 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, वहीं 10वीं कक्षा में 953777 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में भाग लिया था। अब बोर्ड की ओर से इन सभी की कॉपियों की जांच की जा रही है। इसी सप्ताह मूल्यांकन कार्य पूरा होने का अनुमान है। मूल्यांकन होने के बाद छात्रों का एक रिजल्ट तैयार करने में 10 दिनों का समय लगेगा। ऐसे में अब रिजल्ट मई माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है।

तेज धूप के साइड इफेक्ट : तेज बोलना, नींद की कमी; समझने की क्षमता कम होती

ओपीडी में बढ़े 15 फीसदी बायपोलर डिसऑर्डर केस

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। धूप अब सिर्फ झुलसा नहीं रही, सोचने-समझने की ताकत भी चुरा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी से दिमाग के न्यूरो ट्रांसमीटर पर असर पड़ रहा है, जिससे बायपोलर डिसऑर्डर के मेनिया केस तेजी से सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि हमीदिया अस्पताल के मनो रोग विभाग की ओपीडी में ऐसे केस अप्रैल माह में 15 फीसदी तक बढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अधिक तापमान दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर को प्रभावित करता है। जिससे बायपोलर डिसऑर्डर के मेनिया फेज के केस बढ़ते हैं। इन मरीजों में तेज़ बोलना, नींद की कमी और निर्णय लेने की क्षमता का कमजोर होना प्रमुख लक्षणों के रूप से देखे जा रहे हैं। बायपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। जिसमें व्यक्ति के मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। यह दो तरह का होता है। जिसमें पहला मेनिया है। इसमें व्यक्ति उत्साह और ऊर्जा की अधिकता महसूस करता है। यह तब होता है जब व्यक्ति तेज धूप के संपर्क में ज्यादा रहता है। जिसमें समय पर इलाज ना लिया जाए या सावधानी ना रखी जाए तो यह एक्यूट मेनिया का रूप ले सकता है। वहीं, बारिश या ठंड में जब धूप कम होती है तब इसके दूसरे रूप डिप्रेशन के मामले बढ़ते हैं। जिसमें उदासी और ऊर्जा की कमी के एपिसोड शामिल होते हैं।

यह है बायपोलर डिसऑर्डर के शुरुआती लक्षण
उत्साह और ऊर्जा की अधिकता
अधिक बात करना और तेजी से बोलना
विचारों की अधिकता और तेजी से बदलते विचार
जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होना
नींद की कमी और अत्यधिक गतिविधि
गंभीर अवस्था में दिखते हैं यह लक्षण
हैलुसिनेशन- ऐसी आवाजें सुनना या चीजें देखना जो असल में नहीं होती हैं।
डिल्यूजन्स- झूठे, गलत लेकिन मजबूत ख्यालों का आना। जैसे मैं भगवान हूं, मुझमें विशेष शक्तियां हैं या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है।
निर्णय क्षमता का खत्म होना। कई दिनों तक न सोना, फिर भी थका हुआ महसूस न करना।
गुस्से के तेज झोंके आना और बात बात पर लड़ाई-झगड़ा करना।

बचाव के उपाय
कोशिश करें कि तेज धूप में ना निकलें। जरूरी हो तो चश्में, टोपी और गमछे का उपयोग करें।
पर्याप्त पानी पीएं।
खुद को शांत रखने का प्रयास करें और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें।
यदि शुरुआती लक्षण नजर आएं तो बिना देरी करे विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें।

इन दिनों बायपोलर डिसऑर्डर व एंग्जाइटी का खतरा ज्यादा
गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रुचि सोनी के अनुसार, गर्मी में दो रोग बायपोलर डिसऑर्डर और एंग्जाइटी के केस ज्यादा बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ने पर सूर्य की रोशनी तेज होती है। जिससे न्यूरो ट्रांसमीटर पर असर पड़ता है और बायपोलर डिसॉर्डर के मरीज मेनिया फेज में चले जाते हैं। जो इस रोग के पुराने रोगी हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। वे दवा समय पर खाएं, पर्याप्त नींद जरूर लें, खुद को हाइड्रेट रखें और तेज धूप में ज्यादा देर से बचें।

भोपाल में नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद

भोपाल। भोपाल की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमुदिनी पटेल ने 14 साल की नाबालिग को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने मामले में पैरवी की थी। आरोपी शरीफ अता ने 9 दिसंबर 2019 को पीड़िता को गोविंदपुरा इलाके से अगवा किया था। उसे सीहोर ले जाने के बाद एक कमरे में बंधक बनाकर ज्यादती की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।
9 दिसंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने गोविन्दपुरा थाने पहुंचने के बाद बताया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी शरीफ अता दूध लेने का कहकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से ही आरोपी नहीं लौटा था। शरीफ अता पीड़िता के भाई के दोस्त का मुंह बोला चाचा था। जो घटना के आठ दिन पहले से पीड़िता के घर में रह रहा था।

बच्ची को सीहोर से रिकवर किया गया था
दो दिन बाद पुलिस ने बच्ची को सीहोर से दस्तयाब किया था। तब पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि आरोपी उसे दूध दिलाने का बोलकर साथ ले गया। जबरन नादरा बस स्टैंड तक ले गया और वहां से सीहोर लेकर चला गया। वहां एक बूढ़ी अम्मा के कमरे में उसे बंधक बनाकर रखा और गलत काम किया। बयानों के आधार पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (3) भादवि 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

आरटीओ ने जब्त की एलपीजी से दौड़ रही 6 गाड़ियां, 18 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला

भोपाल। भोपाल में बुधवार को परिवहन विभाग ने एलपीजी से दौड़ रही 6 गाड़ियों को जब्त किया। इन वाहन मालिकों से 18 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड ने यह कार्रवाई की। अनधिकृत रूप से एलपीजी गैस से संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 ऐसे वाहनों को जब्त किया गया, जो अवैध रूप से एलपीजी का उपयोग कर रहे थे। इन वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के परिसर में खड़ा कराया गया है। इसके अलावा अन्य नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18000 रुपए जुर्माना वसूला। तीन टीमों ने यह कार्रवाई की।

रचना नगर, गौतम नगर-रोहित नगर में आज बिजली कटौती : भोपाल के 50 इलाकों में असर

भोपाल। भोपाल के करीब 50 इलाकों में गुरुवार को 30 मिनट से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। यहां बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी, उनमें रचना नगर, गौतम नगर, रोहित नगर, नारियल खेड़ा, जनता क्वार्टर, बैंक कॉलोनी, वैशाली नगर, आशीर्वाद कॉलोनी, ज्योति नगर समेत कई बड़े रहवासी इलाके भी शामिल हैं। ऐसे में लोग जरूरी काम पहले से निपटा लें। ताकि, बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें परेशान न होना पड़े। इन इलाकों में पड़ेगा असर-सुबह 6 से 6.30 बजे तक रचना नगर, कस्तूरबा नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी एवं आसपास। सुबह 10 से 11 बजे तक सनखेड़ी, सिद्धि सैफरान सिटी, राजहर्ष ए सेक्टर, बांसखेड़ी, सिटी विस्तार कॉलोनी एवं आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ग्लोबल पार्क सिटी, संत आशाराम फेस-3, कंट्री स्काय एवं आसपास के इलाके। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कमला नगर, बापू नगर, ऋषि परिसर, वैशाली नगर एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक फिरदोस नगर, शीतला नगर, निशातपुरा, श्री नगर, सरदार नगर, नारियल खेड़ा एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक समरधा टोला, रिदम पार्क, दीपड़ी, सिग्नेचर एस-9 कॉलोनी, लिबर्टी कॉलोनी एवं आसपास के इलाके। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विश्वकर्मा नगर, जनता क्वार्टर, हनीफ कॉलोनी, संजीव नगर, पुलिस हाउसिंग हाइट्स एवं आसपास के क्षेत्र। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक स्वर्ण कुंज, नर्मदा अपार्टमेंट, रजत गोल्डन एवं आसपास के क्षेत्र। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रोहित नगर, कम्फर्ट होम्स, ज्योति नगर, समर्थ कॉलोनी, स्काय विला, आशीर्वाद कॉलोनी एवं आसपास।

डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, बियर कंपनी के 15 कर्मचारी घायल

चार कर्मचारियों की हालत गंभीर

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। भोपाल-नर्मदापुरम रोड पर बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के सामने एक कंपनी की बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में बस में सवार ड्राइवर-कंडक्टर सहित सोम डिस्टिलरीज के करीब 15 कर्मचारी घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद राहगीरों और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को घटना स्थल के पास ही स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। ड्राइवर हेमंत, मनोज

यादव और अनिल मीणा की हालत चिंताजनक है। वीडी शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हालत भी गंभीर है, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाग सेवनिया टीआई अमित सोनी के मुताबिक बीयू के सामने बस बेकाबू होने के बाद डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2:35 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही थाने से करीब 15 जवानों को मौके पर रवाना किया गया।
दूसरी बस के ओवरटेक करने से संतुलन बिगड़ा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस सोम डिस्टिलरीज के कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। तभी दूसरी बस ने ओवरटेक की कोशिश की। हादसे का शिकार बस उसके बेहद करीब थी। ड्राइवर ने बचने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा दिया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

घायल बोले- दूसरी बस के चक्कर में हादसा हुआ
बस में सवार जगदीश नाम के व्यक्ति ने बताया कि आनंद नगर से मंडीदीप जा रहे थे। दूसरी बस ने ओवरटेक करते समय हमारी बस को दबाया, हमारी बस भी स्पीड में थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, नहीं लगे, तब उसने बस को फुटपाथ पर चढ़ा दिया।

हादसे के बाद ट्रैफिक जाम के हालात बने
हादसे के बाद करीब डेढ़ घंटे तक बीयू से मंडीदीप की ओर जाने वाली सड़क पर जाम के हालात रहे।
हालांकि पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।

सम्पादकीय

अमेरिका और चीन के बीच ट्रैरिफ वार और भारत

अमेरिका ने चीनी सामान के आयात पर 245 पर्सेंट के टैरिफ का ऐलान किया है। अब तक यह 145 फीसदी लग रहा था, लेकिन जब चीन ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए चीनी आयात पर टैरिफ 125 फीसदी तक कर दिया तो अमेरिका ने भी इसमें इजाफा किया है। वाइट हाउस की ओर से मंगलवार देर रात यह जानकारी दी गई है कि चीनी सामान के आयात पर अब 245 फीसदी का टैरिफ लगेगा। अब तक चीन पर 145 पर्सेंट का टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को इसमें एक साथ 100 पर्सेंट का इजाफा कर दिया गया। अमेरिका की ओर से यह फैसला बेहद सख्त है, जबकि उसने भारत समेत तमाम देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक लिया है। दरअसल ऊर्जा से लेकर विमानन और रक्षा तक कई क्षेत्रों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के नियंत्रण को लंबे समय से वैश्विक जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका ने चीनी सामान के आयात पर 245 पर्सेंट के टैरिफ का ऐलान किया है। अब तक यह 145 फीसदी लग रहा था, लेकिन जब चीन ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए चीनी आयात पर टैरिफ 125 फीसदी तक कर दिया तो अमेरिका ने भी इसमें इजाफा किया है। वाइट हाउस की ओर से मंगलवार देर रात यह जानकारी दी गई है कि चीनी सामान के आयात पर अब 245 फीसदी का टैरिफ लगेगा। अब तक चीन पर 145 पर्सेंट का टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को इसमें एक साथ 100 पर्सेंट का इजाफा कर दिया गया। अमेरिका की ओर से यह फैसला बेहद सख्त है, जबकि उसने भारत समेत तमाम देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक लिया है। दरअसल ऊर्जा से लेकर विमानन और रक्षा तक कई क्षेत्रों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के नियंत्रण को लंबे समय से वैश्विक जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी निर्यात पर प्रतिबंधात्मक उच्च टैरिफ लागू किए जाने के बाद चीन के नेताओं ने भी इस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल आरंभ कर दिया है जिसके बारे में लंबे समय से आशंकाएं प्रकट की जा रही थीं। चीन ने निर्यातक के पास समुचित लाइसेंस न होने की स्थिति में 7 दुर्लभ खनिजों का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। चीन के पास 17 ऐसे खनिजों की सूची है। अधिकांश निर्यातकों ने ध्यान दिया कि फिलहाल वहां प्रभावी लाइसेंसिंग व्यवस्था नहीं है और कम से कम निकट भविष्य में इसका मतलब निर्यात पर प्रतिबंध लगने जैसा ही है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन के अधिकारी वास्तव में कोई निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकार गठित करना चाहते हैं और उसे इतना क्षमता संपन्न बनाना चाहते हैं जो निर्यात की जांच परख कर सके? अगर वे ऐसा चाहते भी हैं तो इससे व्यवस्था में तनाव उत्पन्न होगा और संभव है कि चीन के अफसरशाह उन देशों के ग्राहकों और कंपनियों को निशाना बनाएं जो भूराजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है लेकिन उसके साथ-साथ यूरोपीय देश और भारत भी जद में आ सकता है। ऐसे निर्यात नियंत्रण अब उन चुंबकों पर भी लागू होंगे जिनका निर्माण दुर्लभ खनिजों से होता है और जो वाहन और रक्षा क्षेत्र सहित कई तरह के विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं। कम से कम 2010 से यह बात ज्ञात है कि चीन चुनिंदा अहम खनिजों पर एकाधिकार करना चाह रहा है और वह इस एकाधिकार का इस्तेमाल आर्थिक दबदबा कायम करने के लिए करेगा। यही वह साल था जब चीन ने पहली बार इसे हथियार की तरह बरतते हुए अहम भू-खनिजों का जापान की कंपनियों को किया जाने वाला निर्यात रोक दिया था। उस समय दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ था। तब से अब तक अन्य देशों के पास पर्याप्त अवसर था कि वे वैकल्पिक क्षमताएं विकसित कर लेते। दुर्भाग्यवश कई देशों में अलग-अलग नए नीतिगत मिशन स्थापित होने के बावजूद और अमेरिका के पिछले प्रशासन द्वारा ढेर सारी धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद इसके आपूर्ति शृंखला पर चीन का प्रभावी नियंत्रण बरकरार है। अमेरिकी कंपनियों ने खासतौर पर अक्षम्य आलस्य बरता है। इसके वैश्विक परिणाम बहुत परेशानी खड़ी करने वाले हो सकते हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रिक कारों को अपना रही कार कंपनियों को अहम चुंबक हासिल करने में संघर्ष करना होगा। इसी तरह ड्रोन, रोबोटिक्स और मिसाइल विनिर्माण को भी आपूर्ति क्षेत्र की दिक्कतों का सामना करना होगा। इसका असर पश्चिमी देशों की सैन्य तैयारियों पर पड़ेगा। खासतौर पर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध और अटलांटिक पार के तनावों के कारण समूचे यूरोप में हथियारों के जखीरे तैयार हो रहे हैं। ये चिंताएं भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भी कई को परेशान करने वाली हैं। सरकार ने देश में दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति के लिए लंबे समय तक सरकारी क्षेत्र पर भरोसा किया।

और कितने मुर्शिदाबाद ?

नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा जल रहा है। त्रिपुरा तक में इस आग में जानबूझकर घी डालने का काम किया गया है। बड़ी बात बात यह है कि देश की संसद से पास एक कानून के नाम पर भड़की हिंसा को रोकने के लिए जिन नेताओं से इसके लिए शांति की अपील की उम्मीद होनी चाहिए थी, वही इसे और भड़काने में लगे हुए हैं। इस काम में बड़ी पार्टियों के नेता लगे हुए हैं और वोट बैंक के चक्कर में कोई उन्हें जुबान बंद रखने तक की कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। कई रिपोर्ट कहती हैं कि पिछले साल उपद्रवियों ने जो हालात बांग्लादेश में बना दिए थे, कुछ समाज विरोधी लोगों ने आज वैसी ही स्थिति मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई जिम्मेदार नेता इन दंगों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहा है या दे चुका है तो उसपर कार्रवाई कब होगी?

नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा जल रहा है। त्रिपुरा तक में इस आग में जानबूझकर घी डालने का काम किया गया है। बड़ी बात बात यह है कि देश की संसद से पास एक कानून के नाम पर भड़की हिंसा को रोकने के लिए जिन नेताओं से इसके लिए शांति की अपील की उम्मीद होनी चाहिए थी, वही इसे और भड़काने में लगे हुए हैं। इस काम में बड़ी पार्टियों के नेता लगे हुए हैं और वोट बैंक के चक्कर में कोई उन्हें जुबान बंद रखने तक की कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। कई रिपोर्ट कहती हैं कि पिछले साल उपद्रवियों ने जो हालात बांग्लादेश में बना दिए थे, कुछ समाज विरोधी लोगों ने आज वैसी ही स्थिति मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई जिम्मेदार नेता इन दंगों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहा है या दे चुका है तो उसपर कार्रवाई कब होगी?
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को ही आरोप लगाया था कि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जो नंगा नाच किया गया है उसके लिए सीधे तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तरदायी हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ही विरोध करने के लिए लोगों को कहकर और यह दावा करके कि वह संसद से पारित कानून को लागू नहीं करेंगी, साफ तौर से हिंसा भड़का रही हैं।
रिजिजू अकेले नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पार्टी के पूर्व पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी वक्फ कानून को लेकर हो रही घटनाओं के लिए सीधे-सीधे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से बहुत से लोग गोली लगने से जख्मी हैं, लेकिन पुलिस और सरकार सब कुछ छिपा रही है। इतना ही नहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सूबे की सरकार और पुलिस अगर चाहती तो यह घटना नहीं होती। यह सीधे बंगाल की सरकार की नाकामी है।
एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसा कह रहे हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद जो कुछ कह रहे हैं, उसे बहुत ही भड़काऊ कहा जा सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करेंगे, तो उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्सपर्सन के साथ क्या हुआ?..हमने देखा है गोल्डन टेंपल के साथ क्या हुआ? किसी के मजहबी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी एंटी-मुस्लिम, एंटी-इस्लाम है। उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। वहीं संसद तक में फिलिस्तीन का मामला उठाने वाले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जब बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की घटनाओं के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की गई तो इसपर उनकी अभी तक कोई राय ही नहीं बनी है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि वे बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं। बंगाल सरकार के पास सक्षम लोग हैं और वे आपके सवालों का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। वहीं त्रिपुरा में वक्फ कानून के विरोध में आयोजित एक रैली में शामिल लोगों के हिंसक हो जाने की वजह से जब शनिवार को दो पुलिस वाले जख्मी हो गए तो पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज्जमां की डीआईजी (उत्तरी क्षेत्र) रति रंजन देबनाथ के बीच हो रही बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कांग्रेस नेता सरेआम पुलिस की बड़ी अधिकारी को धमकाते नजर आ रहे हैं।
उन दोनों के बीच की बातचीत कुछ इस तरह से हो रही है- इतना बड़ा क्राउड को कंट्रोल करना....(डीआईजी- जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो भीड़ इकट्ठा क्यों कर लेते हैं...आगे से ऐसा नहीं चलेगा, हम कार्रवाई करेंगे)...देखिए धमकी मत दीजिए। आप मुझे धमकी नहीं दीजिए (डीआईजी-मैं कानून के पालन की बात कर रही हूं, धमकी नहीं दे रही। हजार लोग देख रहे हैं...)....हजार लोग नहीं, हम यहां 50 लाख लोग इकट्ठा कर सकते है। आप वॉर्निंग मत दीजिए। यही नहीं हिंसक भीड़ जुटाने के बावजूद वे वही दुहाई दे रहे हैं कि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
सवाल है कि क्या किसी को माहौल बिगाड़ने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ा जा सकता है कि उसका किसी न किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है? यह देखने वाली बात है कि इन बड़बोले नेताओं पर संबंधित सरकारें कब कार्रवाई करती हैं। नहीं तो बंगाल हिंसा के बीच में जो सियासी खेल चल रहा है, उसकी आग में कितने ही मुर्शिदाबाद झुलस सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से विविधताओं, ध्रुवीकरण और हिंसक टकरावों के लिए जानी जाती रही है। लेफ्ट फ्रंट की दशकों लंबी सत्ता, ममता बनर्जी की उग्र सियासी शैली वाली टीएमसी सरकार और बीजेपी जैसी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बीच ही उभरी है इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) जैसी पार्टी, जो खुद के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती रही है,लेकिन वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इसके समर्थकों ने जिस तरह से बंगाल हिंसा को हवा दी, उससे इसका धर्मनिरपेक्षता वाला चोला पूरी तरह से उतर चुका है।
सोमवार को कोलकाता और दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ इलाके में जो हिंसा फैलाई गई, उसने आईएसएफ के 'शांतिपूर्ण विरोध' के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर आईएसएफ समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इनके समर्थकों ने न केवल पुलिस बैरिकेड तोड़े, बल्कि पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें मोटरसाइकिलें और जेल वैन शामिल थी। शोनपुर मार्केट इलाके में सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, ताकि उपद्रवियों की पहचान छिपाई जा सके, जिसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात करना पड़ा। जब इन प्रदर्शनकारियों को कोलकाता की रैली में जाने से रोका गया, तो हालात बेकाबू ही हो गए। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आईएसएफ विधायक नौसाद सिद्दीकी ने इन घटनाओं को सत्ताधारी टीएमसी की साजिश बताया और भविष्य में भी छह महीने तक शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने की बात कहकर एक तरह से पुलिस-प्रशासन और ममता सरकार को सीधी चुनौती दे दी।
लेकिन सवाल है कि क्या खालिस धार्मिक बैकग्राउंड से निकली किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने के लिए हिंसा और आगजनी का इस्तेमाल करना जायज ठहराया जा सकता है? या इसके धार्मिक अतीत को देखते हुए यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है?
राजनीतिक दल के रूप में आईएसएफ का उदय 2021 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ था। एक मुस्लिम मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई में बनी इस पार्टी ने खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए अपने पहले ही चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ तालमेल किया और संयुक्त मोर्चा बनाया। गठबंधन में इसने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता सिर्फ एकमात्र भांगड़ सीट पर मिली, जहां से नौसाद सिद्दीकी ने जीत दर्ज की। लेकिन, इस चुनाव के बाद गठबंधन में दरार आ गई। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यह टूट गया। तब आईएसएफ के एक कांग्रेस रैली में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के भीतर भी विरोध देखा गया था।
पिछले साल के लोकसभा चुनावों से पहले नौसाद सिद्दीकी ने स्पष्ट कर दिया कि आईएसएफ किसी भी इंडिया ब्लॉक के दल (टीएमसी या कांग्रेस) के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। सिद्दीकी ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बातचीत विफल होने के लिए जिम्मेदार बताया, जिससे यह संकेत निकाला गया कि वह अब खुद को नए विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। एक ऐसा विकल्प जो टीएमसी है, बीजेपी के साथ ही अब कांग्रेस और लेफ्ट से भी अलग है। आईएसएफ का गठन और उसका सामाजिक-धार्मिक प्रभाव पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। एक ओर यह पार्टी खुद को हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज बताती है, वहीं धार्मिक नेतृत्व के हाथ में इसकी कमान और सांप्रदायिक बयानबाजी से यह प्रश्न उठते हैं कि क्या यह पार्टी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है? मौलाना अब्बास सिद्दीकी की भूमिका, पार्टी की गतिविधियों में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल, और वक्फ एक्ट जैसे विषयों पर हिंसक विरोध दिखाते हैं कि पार्टी अपने सेक्युलर नाम से कहीं ज्यादा धार्मिक पहचान की पैरोकारी में जुटी है। आईएसएफ का अब तक का सफर विरोधाभासों से भरा रहा है। एक ओर यह धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, दूसरी ओर धार्मिक पहचान इसकी राजनीति का आधार बन जाती है। एक तरफ यह लोकतांत्रिक विरोध का दावा करती है, दूसरी ओर इसके समर्थक सड़कों पर हिंसा करते नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां धर्म, जाति और वर्ग की राजनीति में गहरी पैठ है, वहां करत्र की भूमिका को केवल एक उभरती पार्टी के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोलकाता की घटनाओं के बाद तो लगता है कि इसके शांति के लबादे और सड़कों पर डायरेक्ट एक्शन की वजह से आक्रोश और अस्थिरता पैदा हो सकती है।

ट्रैक पर बेचैनी: लोको पायलटों की टॉयलेट और भोजन ब्रेक की माँग खारिज, रेलवे के फ़ैसले से नाराज़गी की लहर

एक शांति के पीछे की बेचैनी

रेलवे की पटरी पर दौड़ती हर ट्रेन में समय पर पहुँचने की एक होड़ होती है, पर इस 'समय की सटीकता' के पीछे जो शख्स सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, वो है – लोको पायलट। लेकिन अफ़सोस, इसी लोको पायलट को अपनी ड्यूटी के दौरान एक सबसे मूलभूत सुविधा – टॉयलेट और भोजन ब्रेक – भी नहीं मिलती।
इस असुविधा को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत लोको पायलटों को तब बड़ा झटका लगा, जब रेलवे द्वारा गठित समिति ने उनकी इन माँगों को खारिज कर दिया। समिति ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं है। लेकिन पायलटों का कहना है कि यह मानवता के विरुद्ध और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

एक ड्यूटी, जिसमें साँस लेने की भी फुर्सत नहीं

एक औसत लोको पायलट की ड्यूटी 8 घंटे मानी जाती है, पर ज़मीनी हकीकत यह है कि वे 10 से 14 घंटे तक भी लगातार ट्रेन चलाते हैं।
इस बीच:
उन्हें इंजन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती
खाने के लिए ठहराव का समय नहीं
और टॉयलेट? उसका तो कोई सवाल ही नहीं
जब गर्मी 45 डिग्री हो, और इंजन के अंदर तापमान 50 पार कर जाए, तब ऐसे माहौल में बिना टॉयलेट या ब्रेक के काम करना, किसी यातना से कम नहीं है।

महिला लोको पायलटों की स्थिति और भी कठिन

रेलवे में महिला लोको पायलटों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। लेकिन यह पेशा महिलाओं के लिए आज भी एक कठिन चुनौती बना हुआ है।

अनामिका शर्मा, एक महिला लोको पायलट बताती हैं –
कई बार हमें पानी कम पीना पड़ता है ताकि टॉयलेट न जाना पड़े, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। क्या हम मशीन हैं?
एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं देने से भी पीछे हट रही है।

रेलवे की दलील: सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं

रेलवे समिति का तर्क है कि:
अगर लोको पायलट ड्यूटी के दौरान इंजन छोड़ता है, तो ट्रेन संचालन पर असर पड़ता है
संभावित दुर्घटनाओं का ख़तरा बढ़ सकता है
और मौजूदा इंजन डिज़ाइन में टॉयलेट इंस्टॉलेशन व्यावहारिक नहीं है
यह तर्क कई विशेषज्ञों को अधूरा लगता है।
पूर्व रेलवे सलाहकार डॉ. अजीत पाटिल कहते हैं –
अगर 30,000 फीट पर उड़ता विमान, जहाज और मेट्रो जैसी सुविधाओं में पायलट के लिए टॉयलेट हो सकता है, तो रेल इंजनों में क्यों नहीं?
क्या समाधान मुमकिन नहीं?
निश्चित तौर पर समाधान हैं।
कुछ संभावित उपाय जिनपर रेलवे अमल कर सकता है:
1. ड्यूल लोको पायलट सिस्टम: एक रिज़र्व पायलट इंजन में तैनात हो
2. आधुनिक इंजनों में वैक्यूम या ड्राई टॉयलेट्स लगवाए जाएं
3. लंबी दूरी की ट्रेनों में 5-7 मिनट के ब्रेक पॉइंट्स तय किए जाएं
4. AI या डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे इंजन कुछ मिनट ऑटो-पायलट पर चले
इनमें से कई उपाय रेलवे के कुछ ज़ोन में ट्रायल स्तर पर शुरू भी हुए थे, पर व्यवस्था का अभाव और इच्छाशक्ति की कमी ने इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया।

आंदोलन की आहट

लोको पायलट संगठनों ने चेताया है कि अगर माँगें नहीं मानी गईं, तो वे वर्क-टू-रूल जैसे आंदोलन की ओर बढ़ सकते हैं – जिसमें वे सिर्फ़ अपनी ड्यूटी की अवधि और नियमों तक सीमित रहेंगे। इससे देशभर की रेल व्यवस्था पर असर पड़ना तय है।
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है,
हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, पर क्या हमें जीवन की गरिमा से वंचित किया जा सकता है?

क्या लोको पायलट इंसान नहीं?

देश की जीवनरेखा समझे जाने वाले भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सिपाही – लोको पायलट – इस समय खुद को अनदेखा और अपमानित महसूस कर रहे हैं।
अगर वाकई देश के विकास में उनकी भूमिका अहम है, तो समय आ गया है कि रेलवे सिर्फ नियमों से नहीं, इंसानियत से भी फैसले ले।

रेल मंत्रालय को अब यह तय करना होगा –
क्या सुरक्षा के नाम पर मानवीय अधिकारों को लगातार कुचला जाएगा?
या
क्या समय आ गया है कि लोको पायलट को भी वह सम्मान और सुविधा मिले, जो वह वर्षों से डिज़र्व करता है?
(राजीव खरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)

भारतीय रेल ने शुरू की चलती ट्रेन में एटीएम सुविधा, यात्रियों को मिलेगी नकद निकासी की सहूलियत - लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं

भारतीय रेल ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए यात्रियों के लिए चलती ट्रेन में एटीएम (झरू) की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य यात्रा के दौरान नकद की आवश्यकता महसूस करने वाले यात्रियों को राहत देना है।
रेल मंत्रालय के अनुसार, यह सुविधा फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है और कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ही उपलब्ध कराई गई है। इन ट्रेनों में एक विशेष कोच को एटीएम मशीन के लिए आरक्षित किया गया है। यात्री अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर इस एटीएम से नकद निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी स्टेशन या बैंक एटीएम से करते हैं।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना भारत के प्रमुख बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे देशभर की अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा।
यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे बेहद सुविधाजनक बताया है। खासकर उन यात्रियों के लिए यह सुविधा वरदान साबित हो सकती है जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे होते हैं और जिनके पास कैश खत्म हो जाता है।
हालांकि इस पहल के साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, जिन पर रेलवे और बैंकिंग साझेदार लगातार काम कर रहे हैं।

मुख्य चुनौतियाँ जो रेलवे को झेलनी पड़ सकती हैं:

1. नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या:
भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क कमजोर होता है। ऐसे में एटीएम मशीन को सुचारु रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
2. सुरक्षा की जिम्मेदारी:
चूंकि ट्रेन में नकदी भरा एटीएम मौजूद रहेगा, ऐसे में उसकी सुरक्षा एक अहम विषय है। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और मशीन में विशेष सिक्योरिटी फीचर्स की जरूरत होगी।
3. मेंटेनेंस और कैश रिफिलिंग:
ट्रेन में लगे एटीएम की नियमित देखरेख और उसमें कैश की पूर्ति करना भी एक जटिल कार्य है। इसके लिए अलग से लॉजिस्टिक सपोर्ट और तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होगी।
4. तकनीकी खराबियों से निपटना:
चलती ट्रेन में अगर एटीएम में तकनीकी खराबी आ जाए, तो उसकी तुरंत मरम्मत करना संभव नहीं होता, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।
5. साइबर सुरक्षा और फ्रॉड का खतरा:
डिजिटल युग में एटीएम मशीनें साइबर हमलों का आसान शिकार बन सकती हैं। रेलवे और बैंक को मिलकर इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम करने होंगे।
रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस नई सुविधा के सभी पहलुओं का परीक्षण ट्रायल चरण में किया जाएगा, और प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। मंत्रालय का लक्ष्य है कि भविष्य में सभी प्रमुख ट्रेनों में यह सेवा उपलब्ध कराई जाए।
इस सुविधा से ना केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह भारत में डिजिटल और स्मार्ट ट्रैवल के एक नए युग की शुरुआत भी करेगा।
(राजीव खरे, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ)

दो बड़े नालों को पाटकर अवैध प्लाटिंग के मामले मे

महापौर ने अधिकारियों को दिए ठोस कार्यवाही करनें के निर्देश

सुनील यादव । सिटी चीफ
कटनी, महापौर एवं निगमायुक्त नीलेश दुबे के द्वारा अपने दल बल के साथ माधवनगर पहुंचकर निर्मित अवैध कालोनी में दो बड़े नालों को पाटकर तथा उनका रास्ता डायवर्ट कर नियम विरुद्ध तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मौका निरीक्षण किया गया। इस दौरान महापौर प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त निलेश दुबे को स्थानीय नागरिकों एवं निगम के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि स्थल पर कई दिनों से अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थल पर दो पुराने नालों को पाटकर उनके ऊपर निर्माण करने तथा नाले की दिशा परिवर्तित करने के कारण पानी का बहाव रुक जाने से बारिश के दौरान बस्ती में जलभराव की समस्या उत्पन्न होंगी। जिस पर महापौर एवं निगमायुक्त ने स्थानीय नागरिकों के साथ पूरी अवैध

कालोनी में कराए गए निर्माण कार्यों का पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिशा परिवर्तित नाले से पानी की निकासी बाधित पाए जाने पर निगमायुक्त श्री दुबे ने अवैध कालोनी स्थल के खसरे, भू स्वामी एवं मद आदि की जांच कर दोषियों पर विधि संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्षा काल के दौरान स्थल पर पानी भराव की समस्या न हो इस हेतु अभी से लेआउट के आधार पर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए।

श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित किये जाने एवं पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अर्न्तगत 11.20 करोड की कुल तीन योजनायें स्वीकृत

परियोजनाओं के पूर्ण होने से जनपद में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं में विकास के साथ-साथ पर्यटकों के आवागमन में होगी बढोत्तरी :-जिलाधिकारी मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित किये जाने एवं पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अर्न्तगत 11.20 करोड़ लागत की कुल तीन योजनायें स्वीकृत हैं। जिनमें सहारनपुर के ग्राम जेहरा में प्राचीन पतेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास, विधानसभा गंगोह में स्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं भैरव काली मंदिर का पर्यटन विकास एवं मां शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ में पर्यटन सुविधाओं का सृजन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जनपद में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं में विकास के साथ साथ पर्यटकों के आवागमन में बढोत्तरी होगी। डीएम मनीष बंसल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर के ग्राम

जेहरा में प्राचीन पतेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास हेतु 01.19 करोड़ रूपये की लागत से सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक सुविधाओं का सृजन किया जायेगा। इनमें मुख्य रुप से गेट का निर्माण, यात्रियों के विश्राम हेतु यात्री शेड का निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण, पीने की पानी की व्यवस्था, सोलर लाइटों की व्यवस्था, लैन्डस्केपिंग तथा पार्किंग का निर्माण कराया जायेगा। श्रद्धालुओं के बैठने हेतु बैंचे लगाई जायेंगी। पूजा प्रसाद आदि सामग्री के विक्रय हेतु कियोस्क तथा छोटी दुकानो का भी निर्माण कराया जायेगा। विधानसभा गंगोह में स्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं भैरव काली मंदिर का पर्यटन विकास हेतु कुल 01 करोड़ की लागत स्वीकृत है, जिसके अर्न्तगत यात्री शेड की निर्माण कराया जायेगा, पेवमेन्ट तथा लैन्डस्केपिंग की व्यवस्था होगी। सम्पूर्ण परिसर में पोल लाईटें लगाई जायेंगी तथा एक टॉयलेट ब्लॉक भी निर्मित कराया जायेगा। इसके साथ मां शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ में पर्यटन सुविधाओं का सृजन मां शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ में वृहत स्तर पर पर्यटक सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त कड़ी में ही मां शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ में पर्यटक सुविधाओं हेतु कुल 09.01 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके अर्न्तगत एक मिनी टी0एफ0सी0 (यात्री सुविधा केन्द्र) का निर्माण कराया जायेगा। यहां आकर यात्री विश्राम कर सकेगें व अन्य पर्यटन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगें।

युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण, सृजन बालिकाओं को मिलेगा डिजिटल सशक्तिकरण का अवसर, बड़वानी पुलिस अधीक्षक का प्रेरणादायक कदम

बड़वानी पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने एक अभिनव पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और उन्हें सशक्त बनाना भी है पुलिस अधीक्षक डावर के निर्देशन में आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी प्रतिभाशाली युवा अपने सपनों से वंचित न रह जाए।

शाला त्यागी बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास एसपी डावर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शाला त्यागी (स्कूल छोड़ चुके) बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालयों में भर्ती कराया जाए, ताकि वे फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। सृजन बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त किया जाएगा।दिशा लर्निंग सेंटर द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाए यह पहल बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी कौशल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी अवकाश कालीन दिनों में पुलिस समर कैंप आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है, जिसमें बच्चों और युवाओं को रचनात्मक, प्रेरणादायक और खेल-कूद संबंधी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा, यातायात जागरूकता, महिला सुरक्षा, सृजन बालिका कार्यक्रम जैसे विभिन्न जन-जागरूकता अभियानों में विशेष रुचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महिला सेल डीएसपी महेश सुनैया, आरआई चेतन बघेल, सुबेदार श्रीमती उषा सिसोदिया, महिला थाना प्रभारी श्रीमती सुनिता मुजाल्दा, यातायात प्रभारी विनोद बघेल, साइबर एक्सपर्ट रितेश खत्री, महिला डेस्क प्रभारी एस आई श्रीमती ललीता चौहान, एसआई शीला सोलंकी, एएसआई रेखा यादव तथा काउंसलर श्रीमती अनिता चोयल सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। बड़वानी पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर की यह पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है

महिला आयोग की सदस्या ने की महिला जनसुनवाई

महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ दिए फ़ॉलो अप करने के निर्देश

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, सदस्या, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, लखनऊ श्रीमती संगीता जैन द्वारा सर्किट हाउस सभागार में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाये जाने, महिला उत्पीड़न की रोकथाम व महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से तथा आवेदक व आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से समीक्षा बैठक व महिला जनसुनवाई की गई। मा0 सदस्या द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु जनसुनवाई की गयी जिसमें महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। जिसमें उनके द्वारा 08 प्रकरणों को सुना गया जिसमें से 06 प्रकरण घरेलू हिंसा, महिला थाना तथा 01 प्रकरण शिक्षा विभाग, 01 प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 01 प्रकरण में दोनों पक्षो का समझौता कराते हुए मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी

प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये तथा प्रकरण में फालोअप लेते हुए निस्तारण आख्या से उन्हें अवगत कराने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पाण्डेय द्वारा महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कन्या सुमंगला योजना से अच्छादित बालिकाओं को लाभ दिलाये जाने, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के संबंध में, जनपद में उ0प्र0 बाल सेवा योजना तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी के विषय में जानकारी प्रदान की गयी। मा0 सदस्या द्वारा महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओ के विषय मे समीक्षा की गयी। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मा0 सदस्या द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका, खलासी लाइन का निरीक्षण किया गया, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की क्षमता 100 छात्राओं की है जिसमें 96 बलिकाएं उपस्थित पायी गयी। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक पायी गया। इसके साथ-साथ मा0 सदस्या द्वारा जिला कारागार में महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया जिसमें व्यवस्था ठीक पायी गयी।

जनसुनवाई कार्यक्रम में नगर मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी, गंगोह सुश्री रूचि गुप्ता, श्रीमती रेखा, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रीमती शिवांका गौड, जिला मलेरिया अधिकारी, श्रीमती सुमन गौतम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, श्रीमती नीलम तोमर, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा श्रीमती रेखा कौशिक, बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय श्रीमती बबीता तोमर, प्रभारी निरीक्षक, महिला थाना, श्रीमती श्रीमती सरिता सैनी, सेंटर मैनेजर, सखी-वन स्टॉप सेंटर एवं श्रीमती नेहा शर्मा, जिला समन्वयक, हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन व अन्य कार्मिकों के साथ-साथ जिला प्रोबेशन कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे।

परवलिया के छात्र का चयन राष्ट्रीय स्तर पर चयन

झाबुआ - पी एम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवलिया के कक्षा 11 वी के छात्र उदयसिंह पिता रमेश भूरिया का चयन 19 वर्ष सीनियर 68वी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सेपक टकला इम्फाल (मणिपुर) के लिए हुआ है यह प्रतियोगिता दिनांक 15-04-2025से 21-04-2025के बीच आयोजित होगी छात्र की इस उपलब्धि पर सहायक आयुक्त निशा मेहरा जिला क्रीड़ा अधिकारी कुलदीप धबाई संस्था प्राचार्य एन एस श्रीवास्तव पी टी आई विश्वास शर्मा समसत स्टाफ परवलिया एवं पीटीआई जगत शर्मा राकेश भूरिया कुलदीप सिंह झाला विजय जोशी आदि ने छात्र की उपलब्धि पर बधाई देते हुए उज्वल भविष्य की कामना की

जय बलाई समाज संगठन के तत्वाधान में हुवा डॉ. अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण

मंडलेश्वर - ग्राम ठनगाँव में जय बलाई समाज युवा शक्ति संगठन (जे. बी. एस) के तत्वाधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुवा! कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा जी थे! कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रविन्द्र खाण्डेकर के द्वारा की गई! सर्व प्रथम 11 बजे के करीब ग्राम के मुख्य मार्गो अम्बेडकर मोहल्ला से साईं मंदिर व पीपलचोक होते हुए अतिशीबाजी करते हुए रैली के रूप में यात्रा का नगर भ्रमण किया गया! इसके पश्चात् प्रतिमा का अनावरण कर सभा का आयोजन हुवा जिसमें संथापक सचिन गोयल, संरक्षक प्रदीप साकले, व्यवस्थाप महेश खाण्डेकर, बी. आर खाण्डेकर, हरीश खाण्डेकर, एन आर चाकरे, कमल कानूड़े,दिनेश साहनी आदि के द्वारा अम्बेडकर जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया! सभा में पधारें सभी अतिथियों, वरिष्ठ लोगों, महिलाओं व निर्माण समिति के युवाओं का शाल आदि से सम्मान किया गया! कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी को भोजन आदि भी कराया गया! जिसमें विजय खाण्डेकर,पत्रकार संघ अध्यक्ष भरत राठौड़, पत्रकार सुनील गाडगे, राजेश पंवार, प्रदीप खेड़े, राकेश खेड़े, सुरेश चटर्जी, रमेश दवाड़े शामिल हुए एवं व्यवस्थाओं में पवन खाण्डेकर(जे. बी. एस) ग्राम अध्यक्ष मुकेश खाण्डेकर, कार्यकारी अध्यक्ष विनय खाण्डेकर, संतोष खाण्डेकर, अक्षय खाण्डेकर, लवकेश खाण्डेकर, श्याम भालेकर, विकास हिरवे,सौरभ खाण्डेकर, मिथुन खाण्डेकर, महादेव खाण्डेकर, पाँचीलाल खाण्डेकर ,अनिल खाण्डेकर,देवा खाण्डेकर, फूलचंद वासंदे, प्रशांत सिटोले, दीपक खाण्डेकर, अभिषेक खाण्डेकर, राजा खाण्डेकर, नितिन हिरवे, संजय जगदाले, देवकरण खाण्डेकर,अरुण खाण्डेकर, हरीश खाण्डेकर, कालू खाण्डेकर,कान्हाखाण्डेकर ,राजू भालेकर राज खाण्डेकर, मिथुन खाण्डेकर, बाबू खाण्डेकर सहित अनेक युवाओं ने सहयोग प्रदान किया!

तराना नगर में महिदपुर नाका चौपाटी पर अवैध अतिक्रमण पर चला

तराना- मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर करवाई की जा रही है इसी कड़ी में उज्जैन कलेक्टर द्वारा तराना नगर के आल्ह अधिकारियों को आदेश किया गया था कि नगर में मुख्य चौराहों पर जहां भी अवेध अतिक्रमण किया गया है वह पर बलपूर्वक कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए इसी कड़ी में आज तराना नगर परिषद द्वारा महिदपुर नाका चौपाटी पर अवैध अतिक्रमण को शासन द्वारा तहस-नहस किया गया जिसमें अनेक गुमटियां और दुकान के आगे लगे अतिक्रमण को हटाया गया साहस पूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया तराना एसडीएम राजेश बोरासी, तराना

सीएमओ कैलाश चंद्र वर्मा, तराना एसडीओपी भविष्य भास्कर , तराना नायब तहसीलदार टीना मालवीय और नगर परिषद का अमला मौजूद रहा

माकड़खेड़ा में मुंग की फसल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

जैविक मुंग उत्पादन के लिए कृषक विवेक डोंगरे के प्रयासों की सराहना की

कलेक्टर भव्या मित्तल ने बुधवार को ग्राम माकड़खेड़ा पहुंचकर कृषक विवेक डोंगरे के खेत में लगी मुंग की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जैविक मुंग के उत्पादन और एक साल में तीन फसल लेने के लिए कृषक विवेक डोंगरे की सराहना की । अचानक माकड़खेड़ा पहुंची कलेक्टर ने कृषक विवेक से उनकी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कृषक विवेक ने बताया की प्रति एकड़ 5 क्विंटल मुंग की फसल लेते है और अधिक अच्छी फ़सल होने पर 6 क्विंटल से अधिक भी उत्पादन हो जाता है। हम प्रतिवर्ष ये फ़सल लेते हैं। मुंग की फ़सल मात्र 2 माह की रहती है। यह बिना रासायनिक खाद व दवा के भी अच्छी पैदावार देती है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने विवेक डोंगरे से अन्य फसलों की भी जानकारी भी ली और कहा कि अन्य किसानों को भी जैविक मुंग के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करें।

18-19 अप्रैल को अवकाश के बावजूद सभी उपार्जन केन्द्रों पर होगी गेहूं की खरीदी - खाद्य मंत्री राजपूत

खाद्य मंत्री की सख्त हिदायत, उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

भोपाल। प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केन्द्रों पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

कलेक्टरों को दिए गए निर्देश खाद्य मंत्री राजपूत ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन केन्द्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करें। उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को कतारों में लंबा इंतजार न करना पड़े, तुलाई, रख-रखाव, भुगतान और परिवहन की सभी व्यवस्थाएँ समय पर और पारदर्शिता से हों।

किसानों को न हो कोई असुविधा खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए अवकाश के दिन भी उपार्जन कार्य जारी रखा जाएगा। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उपार्जन केन्द्र से लापरवाही या अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बुरहानपुर के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर परिवर्तन निदेशालय ईडी की दुर्भावना पूर्ण कार्रवाई के विरोध में न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ईडी जैसी कार्रवाई या करवाते हैं और जिसके माध्यम से उनको परेशान करने का काम करते हैं। इसलिए आज हमने तीन बिंदुओं के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एसडीएम पल्लवी पौराणिक को ज्ञापन सोपा जिसमें उन्होंने कहा है कि आप भारत के संविधान के रक्षक है इस गंभीर प्रकरण में स्वत संज्ञान ले और केंद्र सरकार से जवाब करें कि बिना किसी मूल शिकायत के किस आधार पर वर्षों पुराने प्रकरण को पुन: खोलकर विपक्ष के शीर्ष नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है राजनीति की आड़ में लोकतंत्र को कुचलने की साजिश को रोका जाए इस प्रकार कई कार्रवाई पर तत्काल निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच की व्यवस्था हो इस तरह की प्रमुख बातों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, देवेश्वर वीर सिंह, सौरभ कुरैशी, इंज़माम बक्श, भावेश तोमर, बुरहानपुर प्रभारी उत्तम पाल सिंह, इमरान हुसैन हाफिस मंसूरी पार्षद, शाहिद बंदा पार्षद, मुज्जू मीर पार्षद, अब्बास अंसारी पार्षद इन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

नेशनल हेराल्ड मामले मे कांग्रेस ने उठाये सवाल

2011 मे शिकायत 2025 मे चार्जशीट दाखिल, तेरह साल तक क्या कर रही थी सरकार

राजनीतिक प्रतिशोध, बदले की भावना से काम कर रही है केंद्र सरकार

खरगोन- नेशनल हेराल्ड मामले मे कांग्रेस मुखर होकर विरोध कर रही है आज जिला मुख्यालय खरगोन मे पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा ही नेशनल हेराल्ड केस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) के माध्यम से केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है । उन्होंने आगे कहा की राहुल जी की गुजरात मे सक्रियता से सरकार घबरा गई है तभी इस तरह की कार्यवाही की जा रही है । जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक ने सवाल उठाया की वर्ष 2011 मे इसकी शिकायत हुई थी तो आज तक विभाग क्या कर रहा था ? अचानक 2025 मे चार्जशीट क्यों दाखिल करना पड़ी ? साफ है की केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिये बदले की भावना से काम कर रही है । उन्होंने आगे कहा की प्रवर्तन निदेशालय श्वष्ठ ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है जबकि इसमें एक पैसे का भी हस्तांतरण नही हुआ है और ना ही किसी प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है । पुरा मामला फर्जी है । कांग्रेस पार्टी अदालत मे और बाहर सड़कों पर भी इसकी लड़ाई लड़ेगी । विधायक केदार डाबर ने कहा की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गाँधी, सोनिया गाँधी के साथ खड़ी है केंद्र सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही बंद नही की तो और भी बड़ा आंदोलन होगा । प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रवि जोशी के साथ बड़ी संख्या मे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार हाय हाय, सत्ता का दुरूपयोग बंद करो जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा ।

कलेक्टर ने एसडीएम और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया

विदिशा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज बुधवार की प्रात: विदिशा के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय भवन में पहुंचकर यहां संपादित किए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण। उन्होंने एसडीएम व तहसील कार्यालय भवन में संचालित कार्यों का अवलोकन ही नहीं किया बल्कि यहां उपस्थित स्टाफ से संवाद कर कार्यों को संपादन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी मौके पर दिए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में पहुंचने वाले आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो को दृष्टिगत रखते हुए उनकी समस्याओं व आवेदन का हल निकले और वह संतुष्टि जाहिर करें इसके लिए पहल करने के निर्देश समस्त स्टाफ को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय के बाहर रीडर और बाबू सहित अन्य स्टाफ के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा की जाए, ताकि आम नागरिकों को सहूलियतें हों। साथ ही उन्होंने तहसील कार्यालय में पटवारियों की उपस्थिति के संबंध में भी पूछताछ करते हुए पटवारियों की बैठक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र के पटवारी तहसील कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का संपादन करें, जबकि पंचायत क्षेत्र के पटवारी पंचायत में रहकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने एसडीएम और तहसील कार्यालय के विभिन्न कक्षों में पहुंचकर उपस्थित स्टाफ से संवाद कर रिकॉर्ड संधारण पंजी सहित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया और किस तरह में आवेदनों का निराकरण व कार्यों का संपादन करते हैं के संबंध में जाना। उन्होंने न्यायालय तहसील एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार कक्ष, नायब तहसीलदार कक्ष, निर्वाचन शाखा, न्यायालय तहसील, माल जमादार कक्षों के अलावा अन्य कक्षों में पहुंचकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया, विदिशा एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा, तहसीलदार डॉक्टर अमित सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी साथ मौजूद रहे।

व्यक्ति नहीं संगठन की मजबूती से हो रहा विकाश

घिनौदा भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में बोले विधायक चौहान

सरपंच की सक्रियता ओर दूरगामी सोच से विकसित हो रहा गांव

उज्जैन खाचरोद समरथ सेन आपके आशीर्वाद ने मुझे सेवक के रूप मैं चुना और प्रदेश ओर देश भाजपा की सरकार बनी तब जाक 'आज यह विकाश संभव हो पाया है, यह सब भारतीय जनता पार्टी को आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतिफल है ओर पर अभी भी कुछ लोग पार्टी को नहीं व्यक्ति को सर्वपरी मान कर चल रहे है जबकि संगठन ही सबकुछ है, आज जो करोड़ों रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन सम्पन्न हुए है यह सब आपके कारण ही संभव है इसको करने वाला के कुछ भी नहीं हु, यह सब करने वाले को कराने वाले आप ही है, यह बात घिनौदा में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए क्षेत्र के विधायक डॉ तेजबहादुरसिंह चौहान ने कही ! कार्यक्रम के प्रारंभ मां सरस्वती का पूजन अर्चन करते हुए कार्यक्रम की शुरुवात हुई जहा मंच पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक डॉ तेज बहादुरसिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाटीदार, सरपंच श्रीमतीराधा अनोखीलाल पाटीदार, रामलाल धाकड़, लालसिंह बंजारी, सुबोध स्वामी, कन्हैयालाल चंद्रवंशी, अर्जला सरपंच आदि मंचासिन थे ! इनका स्वागत गांव के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया ! कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धाकड़ ओर डॉ चौहान ने सरपंच की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि पंचायतों के पास बहुत से अधिकार है यदि वे सभी का सही उपयोग कर ले तो सक्षम बन सकती है ! कार्यक्रम के 15 लाख रुपए की राशी से निर्मित नाला निर्माण, 24 लाख रुपए की राशी से (बस स्टैंड, पाटीदार धर्मशाला, बालाजी मंदिर, बजरंग व्यायामशाला) में निर्मित सीसी रोड, 2 लाख से व्यायामशाला में चद्दर सेड, 1 करोड़ 76 लाख की नलजल योजना, 50 लाख की लागत से निर्मित पशु चिकित्सालय, 7.5 लाख की लागत से आंगनवाड़ी भवन, 3 लाख 45 हजार की राशी से स्वच्छता परिशर आदि, 3 लाख की लागत से नइ आबादी में सामूहिक परिशर, 11 लाख की लागत से फूल तालाब में स्टॉप डेम का लोकार्पण किया गया हुआ ! वही 65 लाख की लागत से बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र, 15 लाख की सीसी रोड, 5 लाख की लागत से कुआं निर्माण, 5 लाख की लागत से नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्य सम्पन्न हुआ ! इस दौरान घिनौदा से भरतलाल पाटीदार (मंदिर वाले), जगदीश मुकाती, बाबूलाल कांगरा, सत्यनारायण पाटीदार कन्हैयालाल वाणोंलिया, शंकर मुकाती, शंकर गुरु, दुर्गालाल मासाजी, लक्ष्मीनारायण गुरु, दिलीप पाटीदार, नंदू सराफ़ी, रामकिशन चौधरी, गोविंद कांगरा, पुष्कर मुकाती, नानालाल चौधरी, जगदीश कटारिया (पाटीदार समाज अध्यक्ष), राधेश्याम भूत, कन्हैयाला फुँवार, रतनलाल राठौड़, राजू सराफ़ी चंपालाल वानोलिया, रामचंद्र शर्मा, संजू (दवाई वाले), रामलाल वैरागी, उमेश वानोलिया, अंकित पाटीदार, सचिव चंद्रभानसिंह पंवार, बहलोला सरपंच भरत पांचाल आदि उपस्थित थे ! कार्यक्रम का संचालन नानालाल पाटीदार ने किया, सरपंच प्रतिनिधि अनिलोखीलाल पाटीदार ने घिनौदा की आगामी विकाश योजना का रोड़मेप प्रस्तुत किया पूर्व सरपंच प्रतिनिधी दिलीप पाटीदार ने व्यक्त किया !

स्वेच्छानुदान राशी का सदुपयोग कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भाजपा उज्जैन ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम देख रहे है कि विधायक की स्वेच्छानुदान राशी दिव्यागो को, विभिन्न संस्थाओं को, ओर खेल को प्रोत्साहन देने के लिए युवाओं को मिल रही है ओर डॉ साहब पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने अपनी स्वेच्छानुदान राशी को अच्छी जगह खर्च किया है नहीं इसके पहले के विधायकों ने इसको किस पर खर्च किया किसी को नहीं मालूम पर इस बार डॉ साहब ने अपनी इस निधि को जरूरत मंडो के साथ युवाओं, ओर विभिन्न समितियों को प्रदान किया यह वास्तव में एक नवाचार है !

भाजपा है तो हम ओर विकाश है कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाटीदार ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम करोड़ों रुपए के विकाश कार्यों का लोकार्पण ओर भूमि पूजन कर रहे है ओर आगे भी बड़े बड़े कार्यों को करना हमारा लक्ष्य हेबर यह चलता रहेगा किंतु यह सब विकाश जब तक भाजपा है तब तक ही संभव है इसलिए है भाजपा को मजबूत करना पड़ेगा आपने घिनौदा के बारी मंच से कहा कि वर्तमान के यहां से संगठन की बैठकों में उपस्थित शून्य के बार या नाम मात्र की रहती है जोकि चिंता का विषय है इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है, केवल विकाश से कुछ नहीं होगा

ग्राम पंचायत गुंदरई में कलेक्टर ने किया स्कूल, पंचायत और खरीदी केंद्रों का निरीक्षण

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने ग्राम पंचायत गुंदरई में माध्यमिक स्कूल, पंचायत और विभिन्न खरीदी केन्द्रों का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत गुंदरई में माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण और पंचायत में कराये जा रहे राशन प्राप्त करने के लिए ई- केवायसी का कार्य देखा। कलेक्टर श्रीमती पटले ने माध्यमिक स्कूल के निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गुंदरई में सुगमता से राशन प्राप्त करने के लिए 25 अप्रैल तक चलाये जा रहे ई- केवायसी का कार्य देखा। उन्होंने कहा कि जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्रतिमाह खाद्यान्न प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त हितग्राहियों को व उनके परिवार के सभी सदस्यों का ई- केवायसी करना आवश्यक है। इस दौरान कलेक्टर ने यहां जल गंगा संवर्धन अभियान में किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से उन्होंने निर्देश दिये कि जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से कराये जायें।

कलेक्टर ने किया विभिन्न खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण

कलेक्टर ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें पुख्ता रखने के दिये निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने गुंदरई में श्री शक्ति वेयर हाऊस, गोहचर में शिव शक्ति वेयर हाऊस, गोटेगांव में सांईश्रद्धा वेयर हाउस, कंजई गर्रा रोड में राव वेयर हाउस और रामनिवारी में समृद्धि वेयर हाऊस का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां गेहूं, चना व मसूर उपार्जन का कार्य देखा।उपार्जन कार्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की सहूलियत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें खरीदी केन्द्रों में पुख्ता रहनी चाहिये। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि वे शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही एफएक्यू गुणवत्तायुक्त उपार्जन किया जाये। खरीदी केन्द्रों में संबंधित कर्मचारी समय पर उपलब्ध रहें और अपना काम सुचारू रूप से सम्पादन करते रहें। कलेक्टर श्रीमती पटले ने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें, किसानों को बैठने, पेयजल, छाया, पंखा आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई

खरगोन जिले के गोगावा में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खरगोन द्वारा आयोजित कार्यक्रम बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह विशेष अतिथि तनिष्क कटारिया राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य , सुनील बैरसिया, प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्तेय कार्यक्रम संयोजक सुनील चौहान जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी खरगोन दीपक अटोदे अध्यक्ष सहित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए

एक्टर-राजनेता विजय के खिलाफ फतवा जारी

आरोप- इफ्तार पार्टी में शराबी-जुआरियों को बुलाया

तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख थलापति विजय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चश्मे दारुल इफ्ता के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विजय पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है।

मौलाना ने लगाए गंभीर आरोप

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवे में कहा कि विजय ने अपनी फिल्मों और हाल के इफ्तार आयोजन के जरिए मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने विजय की 2022 की फिल्म बीस्ट का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ा गया था। मौलाना ने कहा, विजय ने अपनी फिल्मों में मुस्लिमों को राक्षस और शैतान की तरह दिखाया। अब राजनीति में उतरने के लिए वह मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जो सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति है।

इफ्तार पार्टी पर उठाए सवाल

इसके अलावा मौलाना ने 8 मार्च को चेन्नई के वाईएमसीए ग्राउंड में विजय की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आयोजन में शराबी और जुआरी शामिल थे, जो न तो रोजा रख रहे थे और न ही इस्लामी नियमों का पालन कर रहे थे। मौलाना ने इसे रमजान की पवित्रता का उल्लंघन करार दिया और तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय से विजय से दूरी बनाने की अपील की।

इफ्तार पार्टी पर पहले भी हो चुकी है शिकायत विजय की इफ्तार पार्टी की शिकायत पहले भी हो चुकी है। 11 मार्च को तमिलनाडु सुन्नत जमात ने चेन्नई पुलिस आयुक्त के कार्यालय में विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। संगठन के कोषाध्यक्ष सैयद कौस ने कहा था, विजय के इफ्तार आयोजन में ऐसे लोग शामिल थे, जिनका रोजा या इफ्तार से कोई लेना-देना नहीं था। यह मुस्लिम समुदाय का अपमान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आयोजन में अव्यवस्था थी और विदेशी सुरक्षाकर्मियों ने मेहमानों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। सैयद ने स्पष्ट किया था कि यह शिकायत प्रचार के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई है।

8 मार्च को किया गया था आयोजन

8 मार्च को विजय ने अपने राजनीतिक दल टीवीके के बैनर तले चेन्नई में एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान वह सफेद पारंपरिक पोशाक और टोपी में नजर आए थे। इस आयोजन में करीब 3,000 लोग शामिल हुए और 15 स्थानीय मस्जिदों के इमामों को भी आमंत्रित किया गया था। विजय के प्रशंसकों ने इस कदम को समावेशी और भाईचारे का प्रतीक करार दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रणनीति के तहत उठाया गया कदम बताया था।

राम चरण-जान्हवी की पेड्डी की शूटिंग पर आया नया अपडेट

मौला अली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है मामला

पैन इंडिया स्टार राम चरण अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म पेड्डी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर राम के प्रशंसक बेहद खुश हो जाएंगे।

पेड्डी की शूटिंग पर अपडेट 123 डॉट कॉम की एक खबर के अनुसार, फिल्म पेड्डी की शूटिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है कि फिल्म की शूटिंग मौला अली स्टेशन पर अब पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि इस जगह पर जगपति बाबू और सत्या के सीन सूट किए गए हैं। इस शूटिंग शैड्यूल के पूरा होने के बाद अब प्रशंसक इसके अगले शैड्यूल के बारे में जानने के इच्छुक हैं।

इस फिल्म में पहली बार नजर आएगी जान्हवी-राम चरण की जोड़ी पेड्डी का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं। इस फिल्म में राम चरण के साथ पहली बार जान्हवी कपूर नजर आएंगी। हालांकि, जान्हवी फिल्म देवरा पार्ट 1 से अपना साउथ डेब्यू कर चुकी हैं। लेकिन राम के प्रशंसक इस फिल्म में उनकी और जान्हवी की रोमांटिक जोड़ी को देखने के लिए उत्सुक हैं।

पेड्डी की स्टारकास्ट राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा फिल्म में शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा जैसे कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। राम और जान्हवी की फिल्म पेड्डी के निर्माण की जिम्मेदारी वृद्धि सिनेमा पर है। वहीं फिल्म को मैथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म का मधुर संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है।

ग्राउंड जीरो में इमरान हाशमी को क्यों किया गया कास्ट ? निर्देशक ने किया खुलासा

इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म ग्राउंड जीरो के निर्देशक तेजस प्रभा विजय देओस्कर ने हाल ही में अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म 2000 के दशक पर कश्मीर में सेट की गई है, जो बीएसएफ अधिकारी नरेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व में एक साहसी मिशन पर आधारित है। नरेंद्र नाथ दुबे ने आतंकवादी 'गाजी बाबा' के खात्मे में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने इमरान हाशमी को क्यों कास्ट किया?

सच्ची घटनाओं पर आधारित है फिल्म बुधवार को एएनआ से बात करते हुए निर्देशक ने कहा कि फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो बीएसएफ अधिकारी नरेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व में हुए महत्वपूर्ण मिशन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से एक वास्तविक घटना पर आधारित है। दुबे जी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ धर दुबे है, कश्मीर में तैनात एक बीएसएफ अधिकारी थे। उन्होंने वहां आठ साल बिताए और लोगों, क्षेत्र और आतंकवादी नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ सीखा। उस दौरान, गाजी बाबा का नाम हर जगह था। वह 2001 के संसद हमले के पीछे का मास्टरमाइंड भी था। वह एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था। दुबे जी ने उसे ट्रैक करने और खत्म करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यह उनके प्रयासों की वजह से ही था कि पूरा ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी, वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देश के सामने यह कीमत कुछ भी नहीं है।'

इसलिए इमरान हाशमी को किया कास्ट इस दौरान निर्देशक तेजस प्रभा विजय देओस्कर ने इमरान हाशमी को मुख्य भूमिका में लेने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वह सेना की भूमिकाओं में एक ही तरह के अभिनेताओं को लेने के सामान्य पैटर्न को तोड़ना चाहते थे। निर्देशक ने कहा, 'हमने 'शंघाई' जैसी फिल्मों में उनका दमदार अभिनय देखा है। उस फिल्म से हमें पता चला कि वह किस तरह के अभिनेता हैं। जब दुबे जी की भूमिका की बात आई, तो मुझे लगा कि हम अक्सर सेना की फिल्मों में अभिनेताओं को टाइपकास्ट कर देते हैं। तो शायद उस में मुझे लगता है कि हम नयापन भूल जाते हैं। जब इमरान का नाम सामने आया, तो मुझे लगा कि वह नयापन लाएंगे। वह एक शक्तिशाली अभिनेता हैं और मुझे यकीन था कि वह भूमिका के साथ न्याय करेंगे।'

एडवांस बुकिंग में केसरी 2 की धीमी रफ्तार, अब तक हुई इतने करोड़ की कमाई

केसरी चैप्टर 2- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इस महीने की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे अभिनीत यह फिल्म अपने ऐतिहासिक विषय और दमदार सितारों के कारण चर्चा में है। हालांकि, एडवांस बुकिंग में इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही है। इसके बावजूद गंभीर विषय और देशभक्ति की भावना के चलते फिल्मी दिग्गज उम्मीद लगा रहे हैं कि यह जल्द रफ्तार पकड़ेगी।

एडवांस बुकिंग में हुई इतनी कमाई सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक केसरी चैप्टर 2 ने पहले दिन के लिए 3,503 शो में 24,935 टिकट बेचे, जिससे 82.85 लाख रुपये की कमाई हुई। वहीं, ब्लॉक बुकिंग और प्रीमियम फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल एडवांस बुकिंग एक करोड़ 86 लाख रुपये रही। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म का मजबूत विषय और अक्षय कुमार की लोकप्रियता इसे वीकेंड पर नई रफ्तार दे सकती है। सकारात्मक चर्चा और देशभक्ति का जज्बा भी फिल्म के पक्ष में जा सकता है।

जलियांवाला बाग की अनकही कहानी केसरी चैप्टर 2 साल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। यह सच्ची घटना पर आधारित एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। जलियांवाला बाग के बाद भारतीय वकील सी शंकरन नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी थी। इस भूमिका में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। वहीं, आर माधवन ने ब्रिटिश पक्ष का बचाव करने वाले वकील नेविल मैककिनले की भूमिका निभाई है। फिल्म में अनन्या पांडे भी सहायक भूमिका में हैं।

किताब पर आधारित है फिल्म

फिल्म रघु पलट और पुष्पा पलट की किताब द केस दैट शूक द एम्पायर पर आधारित है। इसे करण सिंह त्यागी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म के जरिए भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं को पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश की गई है।

स्काई फोर्स में दिखे थे अक्षय कुमार वर्क फ्रंट की बात करें तो इस फिल्म से पहले अक्षय कुमार स्काई फोर्स में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ वीर पहाड़िया भी थे। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। फिल्म का बजट ज्यादा होने की वजह से इसका कलेक्शन संतोषजनक नहीं माना गया।

आईपीएल 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराया

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 32वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया है। आईपीएल के 18वें सीजन के पहले सुपर ओवर में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 11 रन बनाए। जिसके जवाब में दिल्ली ने केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की मदद से संदीप शर्मा की 4 गेंदों पर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में 10 अंकों के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल ने 49 और केएल राहुल ने 38 रन बनाए। जबकि ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद) और अक्षर पटेल ने 34-34 रन का योगदान दिया। वहीं आशुतोष शर्मा ने नाबाद 15 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर को दो विकेट मिले, जबकि महीश तीक्ष्णा एवं वनिंदु हसरंगा के खाते में एक-एक सफलता रही। दिल्ली की ओर से मिले 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तूफानी शुरुआत रही। कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने 6 ओवर में 63 रन बनाए। हालांकि तभी सैमसन रिटायर्ड हर्ट हो गए। सैमसन ने 31 रन बनाए। इसके बाद रियान पराग ने क्रीज पर उतरे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सके और आठ रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा ने यशस्वी का अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े तभी यशस्वी 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तब राणा ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 49 रन जोड़े और टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। इश बीच नीतीश राणा भी अपना अर्धशतक पूरा कर आउट हो गए, उन्होंने 51 रन की पारी खेली। आखिर के छह गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी और जुरेल के साथ शिमरॉन हेटमेयर क्रीज पर थे, लेकन मिशेल स्टार्क की धाकड़ गेंदबाजी और एक के बाद एक यॉर्कर ने राजस्थान की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। स्टार्क ने सिर्फ 8 रन दिए, जिससे राजस्थान 20 ओवर में 188 रन ही बना सकी। तब सुपर ओवर की ओर खेल मुड़ गया, जहां दिल्ली ने बाजी मारी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मिचेल स्टार्क ने 1-1 विकेट लिया।

आईएसएसएफ विश्व कप, लीमा - सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण

नई दिल्ली, । लीमा (पेरू) में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बुधवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में चीनी जोड़ी को दी मात स्वर्ण पदक मुकाबले में सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने चीन की कियानसुन याओ और काई हू की जोड़ी को 17-9 के अंतर से पराजित किया। दोनों भारतीय निशानेबाजों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य भेदा और खिताबी मुकाबला अपने नाम किया।कांस्य पदक मुकाबले में मनु-रविंदर हारे कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत की मनु भाकर और रविंदर सिंह की जोड़ी को चीनी निशानेबाजों चियानके मा और यीफान झांग के हाथों 6-16 से हार का सामना करना पड़ा। सुरुचि का दूसरा स्वर्ण, सौरभ को भी व्यक्तिगत कांस्य मंगलवार को 18 वर्षीय सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस स्पर्धा में उन्होंने अपनी सीनियर और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।

इंटर मिलान ने बायर्न म्यूनिख को 4-3 से हराकर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह

मिलान। इंटर मिलान ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 के क्वार्टरफाइनल के रोमांचक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख को 4-3 के एग्रीगेट स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार देर रात सान सिरो स्टेडियम में हुए दूसरे लेग का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन पहले लेग में मिली 2-1 की जीत के चलते इटालियन चैंपियन इंटर ने अंतिम-4 में प्रवेश किया। अब इंटर का मुकाबला सेमीफाइनल में बार्सिलोना से होगा।

लौटारो और पावार्ड के गोल ने इंटर को दिलाई बढ़त बारिश और तेज़ हवाओं के बीच खेले गए इस मुकाबले में पहले हाफ तक दोनों टीमों के बीच गोल नहीं हुआ। हालांकि, दूसरे हाफ में मुकाबला रोमांचक हो उठा। बायर्न के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने 52वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया और मुकाबले को नई जान दे दी। इसके बाद इंटर के कप्तान लौटारो मार्टिनेज ने 58वें मिनट में गोल दागकर इंटर को फिर से बढ़त दिलाई। महज तीन मिनट बाद, बेंजामिन पावार्ड ने एक शानदार हेडर से गोल कर इंटर को निर्णायक बढ़त दिला दी।

डायर ने दिलाई उम्मीद, लेकिन समर ने बचाई जीत 75वें मिनट में एरिक डायर ने बायर्न के लिए हेडर के जरिए गोल कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। इसके बाद बायर्न ने बराबरी के लिए लगातार दबाव बनाया। स्टॉपेज टाइम में हैरी केन का हेडर इंटर के गोलकीपर यान समर ने शानदार तरीके से रोक लिया और यहीं से इंटर की जीत तय हो गई।

सान सिरो में दिखा अलग नज़ारा, ट्रेबल सपना ज़िंदा इंटर मिलान के फैंस ने टिकट की बढ़ी कीमतों के विरोध में शुरुआती 20 मिनट तक स्टेडियम में सन्नाटा बनाए रखा। इसके बाद फैंस ने जोरदार शोर और गानों से अपनी टीम का हौसला बढ़ाया।

इंटर अब 2010 के जोसे मोरिन्हो युग की तरह एक बार फिर से सीरी ए, चैंपियंस लीग और इटालियन कप ट्रेबल जीतने की ओर बढ़ रही है। टीम इस समय इटली की लीग टेबल में नेपोली से तीन अंकों की बढ़त बनाए हुए है और डोमेस्टिक कप के सेमीफाइनल में एसी मिलान से भिड़ने वाली है।

मौत का डॉक्टर: 15 मरीजों को दी घातक दवाएं हो गया पैरालिसिस

सभी की मौत - ऐसे हुआ सनसनीखेज खुलासा

इंटरनेशनल डेस्क. जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने दुनियाभर में सनसनी फैला दी है। यहां एक 40 वर्षीय डॉक्टर को अपने ही मरीजों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह डॉक्टर इन हत्याओं को अपने शौक के तौर पर अंजाम देता था- यानी उसे लोगों को मारने में आनंद आता था।

जहर की तरह असर करने वाली दवाओं से करता था हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर ने सितंबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच 12 महिलाओं और 3 पुरुषों को जानबूझकर घातक दवाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतकों की उम्र 25 से 94 वर्ष के बीच थी। इन दवाओं में एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट्स शामिल थे, जो पहले मरीजों को लकवाग्रस्त कर देती थीं और फिर उनकी मौत हो जाती थी।

सबूत मिटाने के लिए लगाता था आग

हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने कम से कम पांच बार पीड़ितों के अपार्टमेंट में आग भी लगाई। एक ही दिन में दो मरीजों की हत्या करने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें से एक जुलाई 2024 में हुई जब डॉक्टर ने पहले क्रूजबर्ग में 75 वर्षीय पुरुष की और कुछ घंटों बाद न्यूकोल्न में 76 वर्षीय महिला की हत्या की।

बेहद शातिर और चालाक था डॉक्टर

यह डॉक्टर इतना शातिर था कि कई बार वह खुद ही एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को फोन करता था, ताकि लगे कि वह मदद कर रहा है। एक मामले में उसने खुद एक 56 वर्षीय मरीज की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई।

कैसे हुआ पर्दाफाश?

पहली बार अगस्त 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब मामला केवल गैर-इरादतन हत्या का माना गया। इसके बाद जब नवंबर 2024 में चार और संदिग्ध मौतें सामने आईं, तो मामला गंभीर हुआ और फिर हत्या की साजिश सामने आने लगी। अब तक की जांच में पुलिस ने 395 संदिग्ध मौतों की पहचान की है, जिनमें इस डॉक्टर का हाथ होने की आशंका है।

जर्मनी में पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मामला नहीं है जब किसी मेडिकल प्रोफेशनल पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हों। इससे पहले एक मेल नर्स पर 9 मरीजों की हत्या और 26 को जानबूझकर ओवरडोज देने का आरोप लग चुका है। बताया गया था कि वह काम का बोझ कम करना चाहता था और खुद को जीवन-मृत्यु का भगवान मानने लगा था।

अमेरिका में भारतीय छात्र को कोर्ट ने बचाया

ट्रंप प्रशासन के फैसले को दिया बड़ा झटका

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को 21 वर्षीय भारतीय छात्र कृष लाल इस्सरदासानी को देश से निष्कासित (डिपोर्ट) करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह फैसला विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र के वीजा रद्द होने के मामले में आया है।

क्या है पूरा मामला?

इस्सरदासानी 2021 से एफ-1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में हैं और फिलहाल अपने अंतिम सेमेस्टर में हैं। वह 10 मई 2025 को स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले हैं। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, उनकी अकादमिक स्थिति बेहतर रही है और वह नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहते थे। हालांकि, नवंबर 2024 में एक बार से लौटते समय दोस्तों के साथ उनकी एक अन्य समूह से बहस हो गई थी, जिस कारण उन्हें खराब आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, और उन्हें अदालत में पेश नहीं होना पड़ा।

बिना चेतावनी वीजा रद्द

इस घटना के कई महीने बाद, 4 अप्रैल 2025 को विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि उनका *SEVIS* रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया है जिसका मतलब है कि अब उनका वीजा वैध नहीं रहा। *SEVIS* एक सरकारी प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों की निगरानी करती है।आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में नाम आना और वीजा की स्थिति बनाए न रखना वजह बताई गई। हालांकि, इस्सरदासानी को न तो पहले कोई चेतावनी दी गई, न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला। कोर्ट ने कहा- नहीं दिया गया सुनवाई का मौका अदालत ने माना कि छात्र को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला और न ही उन्हें इमिग्रेशन अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी या विदेश मंत्रालय से किसी प्रकार का आधिकारिक संचार मिला। इस फैसले के बाद अब उनकी **निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लग गई है। बता दें कि एफ-1 वीजा अमेरिका द्वारा उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जारी किया जाता है जो किसी विश्वविद्यालय या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में पढ़ाई करने आते हैं।

दर्दनाक हादसा: नाव में आग लगने से 50 लोगों की मौत, सैंकड़ों लापता

इंटरनेशनल डेस्क: उत्तर-पश्चिमी कांगो में आग लगने के बाद एक नाव पलट गई, जिससे कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कांगो नदी में मंगलवार देर रात को यह घटना हुई थी, जिसमें कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं और कई व्यक्तियों को बचा लिया गया है। रेड क्रॉस और प्रांतीय अधिकारियों की सहायता से बचाव दल बुधवार को भी लापता लोगों की तलाश कर रहा है। संबंधित अधिकारी कोम्पिटेंट लोयोको ने 'एसोसिएटेड प्रेस%' को बताया कि मोटर चालित लकड़ी की नाव में लगभग 400 यात्री सवार थे, लेकिन मबंडाका शहर के पास इसमें आग लग गई। उन्होंने बताया कि 'एचबी कोंगोलो%' नामक नाव मतानकुमु बंदरगाह से बोलोम्बा क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में बचाए गए लगभग 100 लोगों को मबंडाका टाउन हॉल में एक अस्थायी आश्रय में ले जाया गया है। वहीं, घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

लोयोको ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब एक महिला नाव पर खाना बना रही थी। उन्होंने बताया कि नाव में आग लग जाने के बाद कई महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग नदी में कूद गए, और उनकी जान चली गई क्योंकि वे तैरना नहीं जानते थे।

कूड़े में मिली पिता की 62 साल पुरानी पासबुक,रातों-रात करोड़पति बन गया

नई दिल्ली/सैंटियागो (चिली). कहते हैं किस्मत कभी भी करवट ले सकती है, और जिंदगी आपको तब भी चौंका सकती है जब आप पूरी उम्मीद खो चुके हों। चिली के एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक धूलभरी पुरानी पासबुक ने उसकी जिंदगी रातोंरात बदल दी। इस शख्स का नाम है हिनोजोसा, जो अब अचानक से करोड़पति बन गए हैं—और वो भी किसी लॉटरी या इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि अपने पिता के छोड़े गए सामान के बीच छिपे खजाने से।

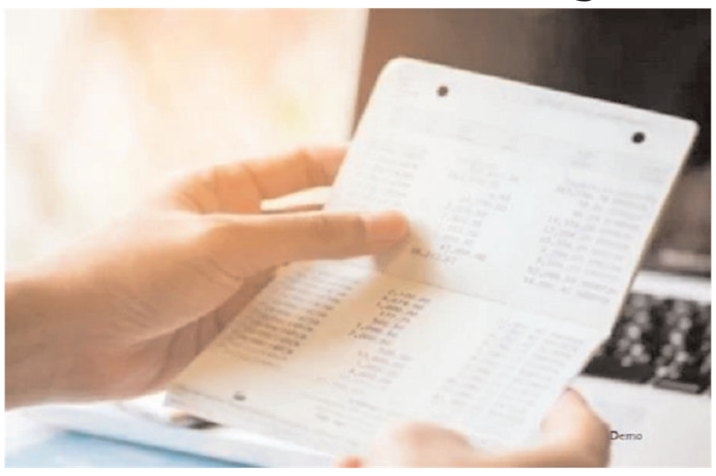

कबाड़ से निकली करोड़ों की कहानी

हिनोजोसा के पिता का हाल ही में निधन हुआ था। पिता की यादों से जुड़े सामान को छंटनी करते वक्त उन्हें एक पुरानी बैंक पासबुक मिली, जो 1960-70 के दशक की थी। शुरुआत में उन्होंने उसे कबाड़ समझकर नज़रअंदाज़ कर दिया, लेकिन बाद में उत्सुकतावश पासबुक को ध्यान से देखा। पासबुक में लगभग 1.4 लाख रुपये (तब की मुद्रा में) जमा होने की जानकारी थी। रकम भले ही छोटी लग रही थी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि पासबुक पर स्टेट गारंटी लिखा था।

क्या है स्टेट गारंटी का मतलब?

स्टेट गारंटी का अर्थ होता है कि यदि किसी बैंक का दिवाला निकल जाए या वह बंद हो जाए, तब भी सरकार उस बैंक के ग्राहकों की जमा राशि की जिम्मेदार होती है। इसका मतलब साफ था—बैंक बंद हो चुका था, लेकिन सरकार अब भी उस रकम को लौटाने के लिए बाध्य थी।

हिनोजोसा ने जब इस रकम के लिए सरकार से संपर्क किया, तो उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। सरकार ने यह कहकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की कि बहुत समय बीत चुका है और बैंक अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हिनोजोसा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई वर्षों चली, लेकिन अंततः न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

10 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक जीत

कोर्ट ने न सिर्फ सरकार को हिनोजोसा को मूल रकम लौटाने का आदेश दिया, बल्कि 62 साल का ब्याज भी जोड़ने को कहा। इस फैसले के बाद हिनोजोसा को करीब 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह फैसला न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि अगर आपके पास दस्तावेज़ हैं, और आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, तो कोई भी व्यवस्था आपके साथ अन्याय नहीं कर सकती।

व्यापार

Gold ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 लाख से बस इतना दूर, एक्सपर्ट ने कहा- जारी रहेगी सोने में तेजी

बिजनेस डेस्क: दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। 10 ग्राम सोना 1,650 की बड़ी छलांग लगाकर 98,100 तक पहुंच गया, यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वैश्विक व्यापार तनाव, खासकर अमेरिका और चीन के बीच, निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर मोड़ रहा है और सोना फिर से सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, अक्षय तृतीया या इसी महीने के अंत तक सोना 1,00,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू सकता है। वो इसे शादी और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक शानदार अवसर मानते हैं।

क्यों बढ़ रही है तेजी

अमेरिका-चीन व्यापार टकराव तेज हुआ है। प्रमुख देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन फिजिकल गोल्ड स्टॉक कर रहे हैं। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी कीमतें चढ़ा रही हैं। स्टॉक मार्केट जैसा बर्ताव कर रहा है सोना

राघवेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि अब सोना भी शेयर बाजार की तरह व्यवहार करने लगा है, कीमतें ऊंची लेकिन स्थिरता की कमी। यह अस्थिरता निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

चांदी भी पीछे नहीं

चांदी की कीमत में भी जोरदार उछाल आया। 1,900 की बढ़त के साथ चांदी 99,400 प्रति किलोग्राम हो गई। यह भी पिछले कुछ सालों का उच्चतम स्तर है। कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चैनवाला कहती हैं कि जब तक व्यापार तनाव खत्म नहीं होता, सोने की यह रफ्तार जारी रह सकती है।

इस बैंक पर फिर चला आयकर विभाग का डंडा, भेजा 244 करोड़ का नोटिस

बिजनेस डेस्क: यस बैंक को एक बार फिर आयकर विभाग की ओर से झटका लगा है। वित्त वर्ष 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग ने बैंक पर 244.20 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स चुकाने का नोटिस जारी किया है। बैंक ने कहा है कि वह इस टैक्स डिमांड को चुनौती देगा और इसके खिलाफ अपील करेगा।

बैंक को दिसंबर 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2016-17 के लिए एक टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला था, जिसमें कुछ जोड़-घटाव किए गए थे। इसके बाद मार्च 2022 में पुनः मूल्यांकन आदेश आया, जिसमें कुछ और बदलाव किए गए थे। बैंक ने दोनों आदेशों के खिलाफ अपील की है और अब पुनः मूल्यांकन के बाद एक नई टैक्स डिमांड आई है।

बैंक ने गलती को बताया, मांगी सुधार की प्रक्रिया

यस बैंक ने कहा है कि पुनर्मूल्यांकन आदेश में एक तकनीकी त्रुटि हुई थी, क्योंकि इसमें टैक्स की गणना रिटर्न में घोषित आय के बजाय असेस्ड आय के आधार पर की गई। इस गलती को सुधारने के लिए 15 अप्रैल 2025 को एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर (सुधार आदेश) पारित किया गया। हालांकि बैंक का कहना है कि इस सुधार आदेश के बाद टैक्स डिमांड में अप्रत्याशित रूप से भारी वृद्धि कर दी गई, जिसे बैंक ने बिना ठोस आधार के बताया है। बैंक ने कहा है कि वह इस अतिरिक्त टैक्स डिमांड को न्यायसंगत नहीं मानता और इसके खिलाफ तत्काल रेक्टिफिकेशन आवेदन दाखिल करेगा। जरूरत पड़ने पर मामला अपीलीय न्यायाधिकरण तक ले जाया जाएगा और बैंक सभी कानूनी विकल्पों का पालन करेगा।

शेयर बाजार में सकारात्मक रुख

दिलचस्प बात यह रही कि इस टैक्स विवाद की खबर के बावजूद बाजार ने बैंक पर भरोसा जताया। बुधवार को दोपहर 3:10 बजे तक यस बैंक का शेयर 2% की बढ़त के साथ 17.87 पर ट्रेड कर रहा था।

क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय न करें ये आम गलती, नहीं तो बढ़ेगा बोझ

बिजनेस डेस्क: आज के समय में क्रेडिट कार्ड का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। खरीदारी से लेकर बिल भुगतान तक, लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे डिस्काउंट ऑफर, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे कई फायदे मिलते हैं। हालांकि, यह समझना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड मूल रूप से एक कर्ज ही है और इसके सही उपयोग न करने पर यह भारी आर्थिक बोझ भी बन सकता है। क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद हर महीने एक बिल बनता है, जिसे तय समय पर चुकाना होता है। कई लोग पूरा बिल भरने के बजाय सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हैं, जो आमतौर पर कुल बकाया राशि का लगभग 5% होता है।

मिनिमम ड्यू समय पर भरने से लेट पेमेंट चार्ज से तो बचा जा सकता है लेकिन यह विकल्प तभी सही माना जा सकता है जब आपके पास फिलहाल पूरी राशि चुकाने के लिए पैसे न हों।

मिनिमम पेमेंट के नुकसान

हालांकि यह विकल्प आपको पेनल्टी से तो बचाता है लेकिन इसके साथ कई वित्तीय जोखिम भी जुड़े हैं-

ब्याज का बोझ- बची हुई बकाया राशि पर हर महीने 3% -4% तक ब्याज लगता है, जो सालाना 30% से 48% तक हो सकता है। यह ब्याज उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है जिस दिन आपने खरीदारी की थी।

क्रेडिट स्कोर पर असर- बार-बार सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर कमजोर हो सकता है, जिससे भविष्य में लोन या क्रेडिट लिमिट बढ़वाने में परेशानी आ सकती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569